https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'भाजपा सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक पार्टी है'

वर्ष-13, अंक-08 16-30 अप्रैल, 2018 (पाक्षिक) ₹20

38वां भाजपा स्थापना दिवस समारोह, मुंबई

चहुंओर कमल ही कमल

भाजपा: देशभक्ति एवं जनसेवा के लिए समर्पित राष्ट्रशक्ति

कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर विशेष

उत्तर-पूर्व अष्टलक्ष्मी बनने की दिशा में अग्रसर

मुंबई में भाजपा स्थापना दिवस पर विशाल रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

ओडिशा में भवानीपटना से बलांगीर की यात्रा के दौरान श्री अमित शाह का स्वागत करते आम जन व पार्टी कार्यकर्तागण

बलांगीर (ओडिशा) में एक विशाल युवा महासम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

मांड्या (कर्नाटक) में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

बादामी (कर्नाटक) स्थित शिवयोगी मंदिर में वीरशैव लिंगायत परंपरा के पूज्य स्वामियों से संवाद करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 सुशासन और विकास से 'अंत्योदय' हमारा लक्ष्य: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भाजपा के 38वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बांद्रा...

वैचारिकी

अर्थ चिंतन 16

श्रद्धांजलि

रवींद्रनाथ टैगोर 18

लेख

भाजपा: देशभक्ति एवं जनसेवा के लिए समर्पित राष्ट्रशक्ति 19

प्रगति की समीक्षा और चर्चा 22

भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई 24

अन्य

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु तीन वर्षों के लिए 4500 करोड़ रुपये मंजूर 15

'राज्य में विकास की नई इबारत लिखने के लिए भाजपा सरकार बनाइए' 26

'ओबीसी समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे' 28

'उत्तर-पूर्व अष्टलक्ष्मी बनने की दिशा में अग्रसर' 30

बीएस-VI ईंधन से वर्तमान बीएस-IV की तुलना में सल्फर का स्तर 80 प्रतिशत घट जाएगा : धर्मेन्द्र प्रधान 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 'भाजपा सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक पार्टी है'

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री...

12 मतभेद की वजह से न रोकें राज्य का विकास: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अप्रैल एवं 5 अप्रैल को ओडिशा का...

सरकार की उपलब्धियां

13 99.49 लाख हुई नए आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से इस दौरान 9.95 लाख...

14 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2017-18 में 7,400 किलोमीटर के ठेके दिये

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय राष्ट्रीय...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

भाजपा न्यू इंडिया की पार्टी है। हम आभारी हैं कि हमें समाज के सभी आयु वर्गों के लोगों का समर्थन मिला है। हम वह पार्टी हैं, जो भारत की विविधता, विशिष्ट संस्कृति और 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति में विश्वास रखती है।

@AmitShah

14 अप्रैल से 05 मई तक भाजपा के सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य एवं पार्षद देश भर के 20 हजार गांवों में जाकर मोदी सरकार की 5 महत्वपूर्ण योजनाएं...सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना और इन्द्रधनुष योजना को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे।

@rsprasad

रूरबन के अन्तर्गत मोदी सरकार में गांव में ऐसा विकास हो रहा है जिसकी आत्मा ग्रामीण की है और सुविधाएं शहर की।

facebook

यह गर्व की बात है कि सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना के तहत अब तक प्रदेश में 12 लाख 30 हजार 360 घरों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जाये। विद्युत कंपनियां अपने अमले का बेहतर प्रबंधन करें। निचले स्तर पर दक्षता बढ़ायी जाये। विद्युत चोरी को रोकने और वसूली बढ़ाने के लिये काम करें।

— शिवराज सिंह चौहान

हमारे बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त हों इसके लिए झारखण्ड सरकार अब स्कूली बच्चों को मुफ्त में दूध पिलायेगी। राज्य के आठ जिलों के करीब एक लाख बच्चों को इस स्कीम का लाभ देने की योजना है। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन दूध उपलब्ध करायेगा। **— रघुबर दास**

पूरा बिहार जानता है कि लोहिया-जेपी का नाम लेकर और समाजवाद का लबादा ओढ़कर 1000 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किसने किया, रेलवे के होटलों के बदले जमीन किसने लिखवायी और गरीबों के नाम पर राजनीति कर अपने परिवार की सात पुश्तों के लिए अरबों रुपए की संपत्ति किसने जुटा ली? **— सुशील कुमार मोदी**

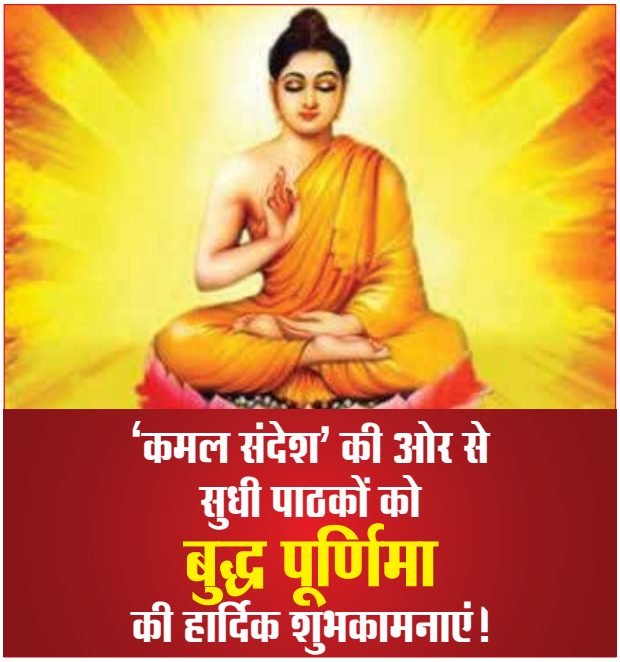

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्यों के प्रति समर्पित भाजपा

6 अप्रैल 2018 को अपने 38वें स्थापना दिवस पर भाजपा अब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्यों के प्रति पुनः अपने आपको समर्पित कर रही है। यह अनेक मायनों में संतोष के साथ अपनी अब तक की यात्रा को देख सकती है। इसकी वैचारिक से लेकर संगठनात्मक और चुनावी उपलब्धियों ने इतिहास के पृष्ठों पर अपनी अमिट निशान छोड़ चुकी हैं। वैचारिक प्रतिबद्धता तथा सैद्धांतिक राजनीति में निष्ठा रखने वाले दल के रूप में भाजपा ने देश की राजनीति में शान से अपना अनूठा स्थान बनाया है। ग्यारह करोड़ से अधिक सदस्यता के साथ आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन बन चुका है। जहां तक चुनावी सफलता की बात है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह स्पष्ट बहुमत से 2014 का लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। ऐसा तीन दशकों के बाद संभव हो सका कि किसी राजनैतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो। इतना ही नहीं, चुनाव–दर–चुनाव जीतते हुए आज देश के 22 राज्यों में इसने स्वयं या सहयोगियों के साथ सरकारें बनाई हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश की जनता अपनी आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रहरी के रूप में भाजपा की ओर देख रही है। यह सब उन लोगों के लिये चमत्कार से कम नहीं, जिन्होंने भाजपा को 2 सीटों से बढ़कर संसद में पूर्ण बहुमत एवं 22 प्रदेशों में सरकार बनाते हुए देखा है। भाजपा ने भारतीय राजनीति का चित्र हमेशा के लिए बदल दिया है और यह देश की राजनीति की धुरी के रूप में उभरी है।

देश में जातिवाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद की विभाजकारी विचारधारा को पराजित कर 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' की राजनीति के पक्ष में वातावरण निर्माण हुआ है। भाजपा के 38वें स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता को मां भारती को परम वैभव पर ले जाने के अपने संकल्प के प्रति स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा।

भाजपा देश में जन–जन के लिये आशा की किरण बनकर उभरी है। स्वतंत्रता के पश्चात् यह अपेक्षा थी कि सदियों की गुलामी से उभरे दागों को कांग्रेस धो देगी, परन्तु जब कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के महान् आदर्शों से विमुख हुई तथा सत्ता केंन्द्रित एवं वंशवादी राजनीति को अपना लिया, तब हर क्षेत्र में यह भ्रष्टाचार, कुशासन, नीतिगत–पंगुता तथा दिशाहीन राजनीति की पर्याय बन गई। यह इस हद तक गई कि इसने देश पर आपातकाल थोपा तथा लोकतंत्र एवं संविधान का गला घोंट दिया। साथ ही, यह एक ऐसी पार्टी के रूप में सामने आई जो येन-केन प्रकारेण सत्ता से चिपकी रहना चाहती है तथा विभाजनकारी राजनीति से भ्रष्टाचार एवं वंशवाद को सींचना अपना परम कर्तव्य समझती है। विदेशी आक्रांताओं के आघातों से त्रस्त भारत के लिये भाजपा एक समाधान के रूप में सामने आई, जिसके ऊपर देश को कांग्रेस के लंबे कुशासन, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता से उबारने का दायित्व है। एक ओर जहां इसने आपातकाल के विरुद्ध गौरवपूर्ण संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लंबी लड़ाई छेड़ी। जब भी इसे जनसेवा का अवसर मिला राज्यों में इसकी सरकारों ने उच्च मानदंड स्थापित किये। गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकारों की उपलब्धियों ने विकास एवं सुशासन के नये आयाम गढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केन्द्र में भाजपा–नीत राजग सरकार ने हर क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियों से देश को एक नई ऊंचाई दी। कांग्रेस–नीत यूपीए के 10 वर्षों के कुशासन, भ्रष्टाचार एवं नीतिगत–पंगुता के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भाजपा नीत राजग को भारी जनादेश दिया। उस समय से देश व्यापक परिवर्तन को देख रहा है ,जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कड़ी मेहनत, भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं दूरदृष्टि वाली नेतृत्व से संभव हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई एवं भविष्योन्मुखी नेतृत्व में देश एक ऊंची छलांग लगाने को तत्पर है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण के लक्ष्य के साथ भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' के पथ पर तीव्रता से अग्रसर है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ठीक ही कहा है कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व जब हमारे पास है, तब यह अवसर है कि भाजपा को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्यों पर तेजी से आगे बढ़ा जाये।

आज देश में जातिवाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद की विभाजकारी विचारधारा को पराजित कर 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' की राजनीति के पक्ष में वातावरण निर्माण हुआ है। भाजपा के 38वें स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता को मां भारती को परम वैभव पर ले जाने के अपने संकल्प के प्रति स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भाजपा स्थापना दिवस समारोह, बांद्रा ईस्ट (मुंबई), महाराष्ट्र

सुशासन और विकास से 'अंत्योदय' हमारा लक्ष्य: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भाजपा के 38वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बांद्रा ईस्ट, मुंबई) के एमएमआरडीए ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सुशासन और विकास से 'अंत्योदय' के लक्ष्य को समर्पित भाजपा की विकास यात्रा पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।

पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को भाजपा की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का बलिदान यदि किसी एक पार्टी ने दिया है तो भाजपा ने दिया है। मैं उन सभी बलिदानी कार्यकर्ताओं को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष श्री रावसाहब दानवे, राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

श्री शाह ने कहा कि 38 साल पहले मुंबई में ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और अपने उद्बोधन में कहा था, "अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा"। उन्होंने कहा कि आज मुझे यह कहते हुए असीम आनंद की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर कोने में कमल ही कमल खिल रहा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा काफी संघर्षपूर्ण, कठिन और परिश्रम की यात्रा रही है। उन्होंने कहा कि अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। कई मनीषी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचने के लिए अपना बलिदान दिया तब जाकर पार्टी का यह स्वरूप जनता के सामने आ पाया है। उन्होंने कहा कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री सुंदर सिंह भंडारी जी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तक समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला ने पार्टी के लिए अपने-आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी

कार्यकर्ताओं के इसी त्याग और समर्पण के बल पर 10 सदस्यों से शुरू हुई पार्टी आज 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके 1400 से अधिक विधायक, 330 से अधिक सांसद, केंद्र में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार और देश के 20 राज्यों में सरकारें हैं।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों की अपनी यात्रा में अपनी संगठनात्मक, राष्ट्र भक्त और सुशासन वाली पार्टी के रूप में छवि बनाने में सफल हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे महान संस्थापक मनीषियों ने हमें सूत्र दिया था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ता का उपभोग करने नहीं बल्कि गरीबों का कल्याण करने के लिए सत्ता को साधन बनाने राजनीति में आई है और इसी सूत्र पर मोदी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन-धन योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना तथा सामाजिक सुरक्षा कवच की योजनाओं से गरीबों के घर में सुख पहुंचाने का काम किया और 'सबका साथ, सबका विकास' के सूत्र को साकार

बाइक रैली

भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकाली। एयरपोर्ट से बीकेसी तक 50,000 वाहनों, जिसमें कार, ट्रक और निजी बसें शामिल थीं, के साथ कार्यकर्ताओं ने शानदार यात्रा निकाली।

किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, इस दिन पार्टी के हजारों कार्यकर्ता देश भर के 20 हजार गांवों में रात्रि निवास करेंगे और गरीबों के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास करेंगे।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि राहुल जी पूछते हैं कि मोदी सरकार ने साढ़े चार सालों में क्या किया? उन्होंने कहा कि राहुल जी, आप मोदी जी से क्या सवाल पूछ रहे हैं, देश की जनता आपसे आपकी चार पीढ़ी का हिसाब मांग रही है, उन्होंने कहा कि देश में चार पीढ़ियों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं को विकास से महरूम रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के घर में गैस पहुंचाने का काम किया है, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से हर घर में शौचालय पहुंचाया है, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली पहुंचाई है, मुद्रा बैंक योजना से स्वरोजगार का अभियान चलाया है और अब देश के लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 करोड़ रुपये का स्वास्थ बीमा उपलब्ध कराकर गरीबों को बहुत बड़ी राहत दी है जबकि कांग्रेस पार्टी आजादी के 70 सालों में भी ये काम कर नहीं पाई। उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त से ही देश के किसान अपनी फसल के उच्च समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे लेकिन कांग्रेस की केंद्र सरकार आंखें मूंद बैठी रहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है जिससे किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए पहले कभी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय नहीं दिया गया था, उरी हमले के बाद 10 दिन के अंदर ही दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया गया और सेना के जवानों ने अपने शौर्य से दुश्मन की सीमा में घुसकर आतंकियों से हमारे शहीद जवानों का बदला लिया। उन्होंने कहा कि उस एक क्षण से ही दुनिया का देश के प्रति देखने का नजरिया बदल गया और पूरे विश्व को इसका आभास हो गया कि भारत हर तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है।

कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस अब झूठ का पुलिंदा फैलाने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी झूठा प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने एससी/एसटी एक्ट को डिमोलिश कर दिया, जबकि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है कि भाजपा सरकार ने आरक्षण ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल जी, आप कान खोलकर सुन लें कि भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण हटाने वाली नहीं है और यदि कांग्रेस पार्टी इस हटाना चाहे, तब भी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को हटने नहीं देगी, यह कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है।

संसद में चल रहे गतिरोध पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती। उन्होंने कहा कि संसद तो विपक्ष ने नहीं चलने दिया, हम तो सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी ने सुनियोजित तरीके से संसद में शोर-शराबा कर संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम

किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि पार्लियामेंट तो छोड़िए, मैं जनता के संसद में खड़ा हूं, आप जहां चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम चर्चा से नहीं डरते क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई थी। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन की यूपीए सरकार के समय 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले हुए जो आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती थीं। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में श्री देवेन्द्र फड़णवीस जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और दोनों सरकारों पर घोटाले का एक भी आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के वक्त कांग्रेस सरकार की किसान-विरोधी नीति के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, जबकि श्री देवेन्द्र फड़णवीस जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में किसानों की आत्महत्या दर में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश, किसानों के खेत में पानी पहुंचाने, भ्रष्टाचार विहीन सरकार चलाने और इंदु मिल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक की रचना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार और देवेन्द्र फड़णवीस सरकार ने किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2019 के लोक सभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की बाढ़ से बचने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आये हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं कि हमें 2019 का लोक सभा चुनाव नारों और खोखले वादों पर नहीं, बल्कि संगठन और मोदी सरकार के काम-काज के आधार पर जीतना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मोदी सरकार की गरीब-कल्याण की योजनाओं को घर-घर पहुंचाएं और चुनाव के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे दो लोक सभा की सीटें हारने पर मिठाइयां बांट रही है। उन्होंने कहा कि हम तो केवल दो लोक सभा की सीट हारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी पार्टी नहीं देखी जो अपनी जमानत जब्त होने पर मिठाइयां बांट रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से देश में हुए लगभग हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश के 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा एवं सहयोगियों की सरकारें हैं, देश के 68% भू-भाग और 70% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में अहर्निश लगी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि यह भाजपा का स्वर्णकाल नहीं है, यह भाजपा का स्वर्णकाल तभी होगा जब ओडिशा और बंगाल में हमारी सरकार बनने के साथ-साथ 2019 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करे और एनडीए की सरकार बने। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नरेन्द्र मोदी सरकार और देवेन्द्र फड़णवीस सरकार की उपलब्धियों को घर-घर में पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भी फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आप तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मिशन है 2022 तक देश को गरीबी, बेरोजगारी, अंधकार और धुएं से मुक्ति दिलाना, हम सब प्रधानमंत्री जी के मिशन को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हों और 'न्यू इंडिया' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें।

इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री आशीष शेलार, महाराष्ट्र राज्य वित्तमंत्री श्री सुधीर मुंगटीवार, राजस्व मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल सहित अनेक वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। ■

समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद

भाजपा सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक पार्टी है : नरेन्द्र मोदी

हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाना है और उनका सशक्तिकरण करना है। हमारी सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य इसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता विपक्ष के लगातार झूठ और दुष्प्रचार को नाकाम करने के लिए 'सत्यमेव जयते' की शक्ति के साथ जनता के समक्ष जाएं और जनता तक हमारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं।

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया के "नरेन्द्र मोदी एप" के माध्यम से देश भर के लाखों ट्विटर फॉलोअर्स को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया।

भाजपा की विकास यात्रा की सफलता में समर्पित कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जनहित के लिए हम संघर्ष करते थे, जबकि आज आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम पूरी तरह समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने, 'न्यू इंडिया' का संकल्प साकार करने और "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र से सर्व-समावेशक राजनीति के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता समर्पण भाव से सक्रिय हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक राजनीति को समर्पित पार्टी है जहां परिवारवाद और जातिवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी की सोच थी कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव कैसे लाया जाये और इसके लिए आपकी भाजपा सरकार

निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री पद की महती जिम्मेदारी सौंपी, तब मैंने यह कहा था कि यह सरकार पूर्ण रूप से गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी और लगातार चार साल से हमने सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किये हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भाजपा सरकार के प्रति विपक्षों का विरोध अधिक तीव्र, उग्र और हिंसक होता जा रहा है, लेकिन इनका कारण हमारी कोई गलती नहीं है, इसका कारण यह है कि विपक्ष हमारी बढ़ती जा रही लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जैसे समाज के हर तबके और समुदाय के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है और हमारी योजनाएं इसकी साक्षी हैं। सन 2022 में, आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पूरे होने के उपलक्ष्य पर हमें "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का संकल्प पूर्ण करना है। उन्होंने कहा कि देश जातिवाद से मुक्त हो, गंदगी से मुक्त हो, सम्प्रदायवाद से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, यही हमारा संकल्प है और यह हमें सिद्ध करना है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर 'न्यू इंडिया' के निर्माण के लिए समर्पित कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की मैं सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि शासक दल के रूप में हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, पहले विपक्ष के रूप में हम जनहित के लिए संघर्ष करते थे, अब सामान्य व्यक्ति की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है।

श्री मोदी ने कहा कि शून्य से शिखर तक की हमारी यात्रा लोकतंत्र

के मार्ग पर ही अविरत चल रही है। देश की बदलती परिस्थिति में हमें सर्व समावेशक और सर्वस्पर्शी राजनैतिक दल के रूप में कार्यरत रहना है। राजनैतिक विपक्ष अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु देश और समाज को तोड़ने के लिए सक्रिय है लेकिन हमें संयम और संयमित कार्य से विरोध को निष्क्रिय बनाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाना है और उनका सशक्तिकरण करना है। हमारी सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य इसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता विपक्ष के लगातार झूठ और दुष्प्रचार को नाकाम करने के लिए 'सत्यमेव जयते' की शक्ति के साथ जनता के समक्ष जाएं और जनता तक हमारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं। ■

मतभेद की वजह से न रोकें राज्य का विकास: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अप्रैल एवं 5 अप्रैल को ओडिशा का प्रवास किया। पहले दिन वे कालाहांडी जिला मुख्यालय भवानीपटना पहुंचे।

भवानीपटना के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित जनसभा में श्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की सफलता तथा राज्य सरकार की नाकामी गिनाई। उन्होंने केंद्र द्वारा ओडिशा को अब तक दी गई मदद का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए प्रदेश सरकार को राज्य की जनता के लिए काम नहीं करने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण ओड़िशा के पास सब कुछ है, केवल एक अच्छा शासक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी का विकास का जो रथ निकला है, वो गली-गली पहुंचने वाला है तथा ओड़िशा में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। एससी/एक्ट को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि हम न तो आरक्षण हटाएंगे और न ही किसी को हटाने देंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सिर्फ तात्कालिक फायदे के लिए योजनाओं पर काम नहीं करती है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में देश के सभी इलाकों का विकास होना चाहिए। लेकिन देश का पूर्वी हिस्सा दशकों से विकास से बेपटरी हो गया था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पूर्वी भारत के उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जो संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि भाजपा कभी भी किसी सरकार के साथ भेदभाव नहीं करती है। दरअसल गैर भाजपा शासित राज्यों की आदत दोष डालने की पड़ चुकी है। केंद्र सरकार का स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं। लेकिन आम लोगों को विकास के मुद्दे पर राजनीतिक दलों को मनभेद से बचना चाहिए। संपूर्ण भारत का विकास ही भाजपा का सपना है।

इस जनसभा को केंद्रीय मंत्री सर्वश्री जुएल ओराम एवं धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री बसंत पंडा, प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा आदि अनेक वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। ■

दलित बंधु के यहां भोजन करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता।

भाजपा कार्यकर्ताओं के हत्यारों को संरक्षण दे रही है पटनायक सरकार

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 अप्रैल को बोलांगीर में कहा कि ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार भाजपा के 14 कार्यकर्ताओं की हत्यारों को संरक्षण दे रही है।

श्री शाह ने पश्चिमी ओडिशा के बोलांगीर कस्बे में 'युवा महासमावेश' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में ओडिशा में भाजपा के 14 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी लेकिन इन हत्याओं से जुड़े किसी भी आरोपी के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल सरकार के संरक्षण के कारण इन हत्याओं के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा के सत्ता में आने पर इन अपराधों के सभी आरोपियों को पकड़ कर उनके खिलाफ मुकद्दमे दर्ज किये जाएंगे। ओडिशा की बीजद सरकार को 'जला हुआ ट्रांसफार्मर' बताते हुए श्री शाह ने लोगों से इस उखाड़ फेंकने और राज्य के विकास के लिए भाजपा को सत्ता में लाने की आह्वान किया।

99.49 लाख हुई नए आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से इस दौरान 9.95 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2016-17 के शुद्ध संग्रह की तुलना में 17.1 प्रतिशत ज्यादा है। प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमान (9.8 लाख करोड़ रुपये) के 101.5 प्रतिशत और प्रत्यक्ष करों के संशोधित अनुमानों (10.05 लाख करोड़ रुपये) के 99 प्रतिशत को दर्शाता है।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वालों की संख्या भी बढ़कर 99.49 लाख हो गई है (30 मार्च, 2018 तक), जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नए आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या 85.51 लाख थी। यह 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2017-18 में सकल संग्रह (रिफंड के समायोजन से पहले) 13 प्रतिशत बढ़कर 11.44 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1.49 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किये गये हैं। कॉरपोरेट आयकर (सीआईटी) के लिए शुद्ध संग्रह की वृद्धि दर 17.1 प्रतिशत और व्यक्तिगत आयकर (एसटीटी सहित) के लिए शुद्ध संग्रह की वृद्धि दर 18.9 प्रतिशत है। हालांकि, यह बात दोहराई जा रही है कि उपर्युक्त आंकड़े अब भी अनंतिम हैं और संग्रह

के अंतिम आंकड़े प्राप्त होने पर इनमें परिवर्तन हो सकता है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न आयकर विभाग में दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। यह 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान दाखिल किए गए आईटीआर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में दाखिल किए गए 3.79 करोड़ आईटीआर की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 में दाखिल किए गए आईटीआर (6.84 करोड़) 80.5 प्रतिशत अधिक हैं। ■

1 अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल प्रणाली का सहज शुभारंभ

जीएसटी परिषद के निर्णय के मुताबिक वस्तुओं की समस्त अंतर-राज्य ढुलाई के लिए 1 अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल प्रणाली अनिवार्य हो गई। जीएसटी व्यवस्था के तहत राष्ट्रव्यापी ई-वे बिल व्यवस्था का क्रियान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से जीएसटीएन द्वारा किया जा रहा है और इसका संचालन पोर्टल यथा https://ewaybillgst.gov.in पर हो रहा है।

पहले दिन ई-वे बिल पोर्टल पर कुल मिलाकर 2.59 लाख ई-वे बिलों का सृजन हुआ। दूसरे दिन अपराह्न दो बजे तक 2,04,563 ई-वे बिल सृजित हुए। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 11,18,292 करदाताओं का पंजीकर ई-वे बिल पोर्टल पर हुआ है। इसके अलावा 20,057 ट्रांसपोर्टरों ने ई-वे बिल पोर्टल पर स्वयं को नामांकित किया है।

करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों की सहायता करने के साथ-साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जीएसटी की केन्द्रीय हेल्पडेस्क ने उन 100 एजेंटों के साथ मिलकर विशेष व्यवस्था की है, जो विशेष कर ई-वे बिलों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके अलावा राज्यों के कर प्राधिकरणों ने स्थानीय भाषा में हेल्पडेस्क का शुभारंभ किया है, जिसका विवरण जीएसटी के पोर्टल पर उपलब्ध है। केन्द्र के साथ-साथ राज्यों के कर प्राधिकरणों ने भी ई-वे बिलों के लिए प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को उपयोगकर्ताओं (यूजर) के मार्गदर्शन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

विभिन्न विधियों (मोड) जैसे कि वेब (ऑनलाइन), एंड्रायड एप, एसएमएस, बल्क अपलोड टूल और एपीआई आधारित साइट-से-साइट के एकीकरण इत्यादि के जरिए ई-वे बिल का सृजन हो सकता है। विभिन्न तरह की खेपों को ढोने वाले वाहनों के लिए समेकित ई-वे बिल को ट्रांसपोर्टरों द्वारा सृजित किया जा सकता है।

ट्रांसपोर्टर अनेक उप-उपयोगकर्ताओं (सब-यूजर) को सृजित कर सकते हैं और उन्हें उनकी भूमिका बता सकते हैं। इस तरह बड़े ट्रांसपोर्टर अपने विभिन्न कार्यालयों को सब-यूजर के रूप में घोषित कर सकते हैं। ई-वे बिल को उस व्यक्ति द्वारा 24 घंटे के अंदर निरस्त किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसने ई-वे बिल सृजित किया है। प्राप्तकर्ता भी ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर अथवा माल प्रेषक द्वारा ई-वे बिल के सृजन के 72 घंटे के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, ई-वे बिल को खारिज कर सकता है। ■

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2017-18 में 7,400 किलोमीटर के ठेके दिये

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 7,400 किलोमीटर के 1,22,000 करोड़ रुपये मूल्य की 150 सड़क परियोजनाओं के ठेके दिये। पिछले 5 वर्षों में एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई सड़क परियोजनाओं की औसत लंबाई 2,860 किमी थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 4,335 किमी थी। इसकी तुलना में, वित्त वर्ष 2017-18 में दी गई परियोजनाओं की लंबाई सबसे उच्च स्तर पर है और एनएचएआई द्वारा 1995 में इसकी स्थापना के बाद से एक रिकॉर्ड उपलब्धि है।

नवंबर 2017 में महत्वाकांक्षी भारतमाला कार्यक्रम की मंजूरी के बाद और नवंबर 2017 में स्वीकृति के लिए नई प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही परियोजनाओं की निविदाएं और ठेके दिये जा रहे थे। नए प्रोटोकॉल के अन्तर्गत, एनएचएआई बोर्ड को ईपीसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए पूर्ण शक्तियां सौंपी गई। इससे एनएचएआई में उच्चस्तरीय परियोजनाओं की मूल्यांकन समिति और लागत समिति को उचित स्थान दिया गया था।

इस अभियान के दौरान, भारतमाला के बाद, लगभग 11,200 किलोमीटर सड़क की लंबाई की 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 232 परियोजनाओं की निविदाएं लगाई गई थीं। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए, कई सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यरत थे और मजबूत निगरानी तंत्र को इस कार्य के लिए लगाया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए दिये गये आंकड़े अभी भी अधिक हो सकते हैं। यह संभावना व्यक्त की जाती है कि लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं अगले वित्त वर्ष 2018-19 के पहले दो महीनों में दे दी जाएंगी। कुल प्रदान की गई परियोजनाओं में से, 43,000 करोड़ रुपये की लागत की 3,791 किलोमीटर लंबाई को ईपीसी मोड पर प्रदान किया गया था। 76,500 करोड़ रुपये की लागत की 3,396 किलोमीटर लम्बाई को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर प्रदान किया गया था और 2,500 करोड़ रुपये की लागत पर 209 किमी को टोल मोड पर प्रदान किया गया था।

दी गई परियोजनाओं में, राजस्थान में 1,234, महाराष्ट्र में 739 किमी, ओडिशा में 747 किमी, उत्तर प्रदेश में 725 किमी, तमिलनाडु में 511 किमी, आंध्र प्रदेश में 504 किमी, कर्नाटक में 468 किमी, गुजरात में 449 किमी, मध्य प्रदेश में 389 किमी, हरियाणा में 331 किमी, बिहार में 232 किमी, झारखंड में 201 किमी, तेलंगाना में 189 किमी, पश्चिम बंगाल में 126 किमी, पंजाब में 120 किमी, जम्मू-कश्मीर में 100 किमी, और शेष अन्य राज्यों में। प्रदान किये गये कार्यों में उपरोक्त उछाल के साथ एनएचएआई ने अक्टूबर, 2017 में सरकार द्वारा अनुमोदित "महत्वाकांक्षी" भारतमाला परियोजनाओं के लिए एक अच्छी शुरुआत की है, जिसे 5 वर्ष (2017-18 से 2021-22) के बहुत ही कठोर लक्ष्य के साथ लागू किया जाना है। ■

ऊर्जा क्षेत्र और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये 344.5 कोयला रेकों की रिकार्ड ढुलाई

कोल इंडिया लिमिटेड ने 28.03.2018 को एक दिन में 2 मि. टन कोयले की ढुलाई का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसमें रेलवे की मदद से सीआईएल के अपने क्षेत्रों से 289.5 रेकों का रिकॉर्ड परिवहन भी शामिल है। निजी कोयला धुलाई केंद्रों और माल भाड़ा गोदामों की आपूर्ति को मिलाकर रेलवे ने 28.03.2018 को 344.05 कोल रेकों की ढुलाई की। कोयला और रेल मंत्रालय के बीच सामंजस्य ने 342 रेकों की प्रति दिन ढुलाई के स्थापित मानक से बेहतर प्रदर्शन भी संभव हुआ, जो कोयले के संकट का सामना कर रहे ऊर्जा क्षेत्र और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये निर्धारित किया गया था।

प्रतिदिन 230 रेक भेजने के लक्ष्य के विपरीत इसी दिन एक दिन में बिजली घरों को 252 रेक भेजने का एक नया रिकार्ड भी बनाया गया। मौजूदा वर्ष में अथक प्रयासों के जरिये रेल के जरिये ऊर्जा क्षेत्र को ढुलाई में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। पिछले 10 दिनों में बिजली घरों को औसत ढुलाई प्रतिदिन के लक्ष्य 1.4 मि. टन ढुलाई से ज्यादा ढुलाई हुई। इसके परिणामस्वरूप बिजली घरों में औसत भण्डार जो कि अक्टूबर 2017 में 7 मि. टन तक गिर गया था, वह कोयले की खपत में तेज वृद्धि के बावजूद बढ़कर 16 मि. टन पहुंच गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु तीन वर्षों के लिए 4500 करोड़ रुपये मंजूर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च को मार्च, 2020 तक जारी रखने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं को मंजूरी दीः

- पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) की योजनाओं के तहत – वर्तमान में जारी परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण रुख (90:10 आधार) और नई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ विशेष विकास परियोजनाएं।
- एनईसी द्वारा वित्त पोषित अन्य परियोजनाओं के लिए – राजस्व और पूंजीगत दोनों ही – 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण आधार पर, मौजूदा रुख के साथ जारी रहेंगी।
- 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) का विस्तार।
- अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर-सी) को क्रियान्वयन के लिए एनईसी को हस्तांतरित किया गया।
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों में सामंजस्य के जरिए संसाधनों का अनुकूलन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव।

गौरतलब है कि एनईसी की मौजूदा योजनाओं के अधीनस्थ परियोजनाएं एनएलसीपीआर (केंद्रीय) और एनईआरएसडीएस पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के सामाजिक–आर्थिक लाभों में वृद्धि करेंगी, जिससे इन लोगों की क्षमताएं और आजीविका बेहतर होंगी।

वर्तमान समय में 72.12 प्रतिशत की मंजूर लागत वाली ज्यादातर परियोजनाओं (840 में से 599 परियोजनाएं) और समस्त जारी परियोजनाओं के लिए लंबित देनदारियों के 66 प्रतिशत (2299.72 करोड़ रुपये में से 1518.64 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण 'एनईसी की योजनाएं–विशेष विकास परियोजना' के जरिए होता है, जिसके तहत चयनित परियोजनाओं के लिए धनराशि को 90:10 आधार पर केन्द्र और राज्य के बीच बांटा जाता है और इसका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ राशि–राजस्व एवं पूंजीगत दोनों ही– को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के आधार पर मुहैया कराया जाता है और क्रियान्वयन राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों के जरिए होता है।

एनईसी की योजना- विशेष विकास परियोजना पहले के 90:10 आधार पर समूह अनुदान की जगह 100 प्रतिशत अनुदान के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। शेष घटक वर्तमान की तरह 100 प्रतिशत केन्द्रीय फंडिंग आधार पर वित्त पोषित होते रहेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एनईसी महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक अंतःराज्यीय सड़कों के उन्नयन के लिए 'उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना- कार्यक्रम संघटक' का भी कार्यान्वयन कर रही है। कार्यान्वयन के लिए एनईसी से डोनर को हस्तांतरित यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित है। इस योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये की एक राशि आवंटित की गई है।

'संसाधनों का अव्यपगत केन्द्रीय पूल-केन्द्रीय [एनएलसीपीआर (केन्द्रीय)] नामक एक अन्य योजना, जो वर्तमान में मेसर्स डोनर द्वारा वित्त पोषित है, माजुली द्वीप में क्षरण नियंत्रण करने वाली अगरतला-अखोरा रेल लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए संबंधित मंत्रालयों/उनकी एजेंसियों को संसाधन उपलब्ध कराती है। इस योजना को भी कार्यान्वयन के लिए एनईसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

पहले, निधियों को राज्य या केन्द्रीय घटक में वितरित करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। अब एनईसी को उपलब्ध कुल निधियों को दो घटकों (राज्य घटक-60 प्रतिशत एवं केन्द्रीय घटक-40 प्रतिशत) में बांट दिया गया है। राज्य घटक का उपयोग प्रत्येक राज्य में मानदंड संबंधी आवंटन आधार पर उनके हिस्से के अनुसार परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। केन्द्रीय घटक के लिए क्षेत्रीय गुण वाली, अंतःमंत्रालयी योजना की आवश्यकता वाली परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। बांस; सूअर पालन; क्षेत्रीय पर्यटन; उच्च शिक्षा; पिछड़े क्षेत्रों में तृतीय स्तर; स्वास्थ्य एवं विशेष युक्ति; आजीविका परियोजना; एनईआर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्तियां; सर्वे एवं जांच तथा एनईआर संवर्द्धन जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की गई है। उपरोक्त के द्वारा, दुहराव को रोकने के लिए डोनर तथा एनईसी के बीच एक स्पष्ट संविभाजन तथा क्षेत्रों के बीच विभाजन सुनिश्चित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के अलावा, गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) के तहत पर्यटन क्षेत्र में बकाया देयताओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालयों से एवं डोनर मंत्रालय से प्रतिनिधियों के साथ स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की तर्ज पर एनईसी की अध्यक्षता में 5-15 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक तंत्र का भी निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं एसएफसी की प्रक्रिया के जरिये दुहराव से बचना है। ■

अर्थ चिंतन

| दीनदयाल उपाध्याय |

घर-गृहस्थी के चक्र में फंसे हुए किसी सामान्य व्यक्ति से जब आप देश, धर्म, साहित्य आदि की चर्चा करें, तो उसके मुख से अनायास ही यह लोकोक्ति सुनने को मिलती है-

भूल गए राग-रंग, भूल गए छकड़ी।
तीन चीज़ याद रहे, नोन तेल लकड़ी ॥

आज के समाज का यही चित्र है, जिसमें बहुजन समाज नोन, तेल, लकड़ी की चिंता में ही सुबह से शाम करते हुए दिन, महीने और वर्ष बिताता हुआ अपने जीवन की घड़ियां काट जाता है। जीवन के शेष प्रश्न उसके सामने कभी प्रमुख रूप से आते ही नहीं। आए भी तो वह उन्हें द्वितीय स्थान देता है।' आधी पोटोबा मग विठोबा' की मराठी उक्ति के अनुसार, वह पहले भोजन और फिर भजन की चिंता करता है, और जब भोजन की चिंता में ही सब समय और शक्ति लग जाती है, तो भजन के लिए अवकाश ही कहां बचता है।

जनसाधारण ही नहीं तो समाज के अग्रणी एवं विचारकों के भी चिंतन का यही प्रमुख विषय रह गया है। 15 अगस्त, 1947 तक देश के सभी आंदोलनों एवं प्रयासों का हेतु था स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वदेशी, खादी और ग्रामोद्योग, नमक और जंगल सत्याग्रह, करबंदी और लगानबंदी जैसे आंदोलन, फंड के आधार पर स्थापित उद्योग, कपड़े और चीनी की मिलों की स्थापना, संरक्षण और अवमूल्यन आदि के प्रश्नों की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण आर्थिक न होकर राजनीतिक था। इनके सहारे हम स्वतंत्रता संग्राम को बल देना चाहते थे। किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हमारे दृष्टिकोण में अंतर आया है। अब हम प्रत्येक प्रश्न को आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि अब हमारा लक्ष्य हो गया है। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम एवं शासन की योजनाएं इसी उद्देश्य से बनाई जा रही हैं। हमारी संपूर्ण शक्ति इसी एक प्रश्न पर केंद्रित है।

साध्य साधन विवेक

आंदोलनात्मक दृष्टि से इस केंद्रीकरण के पक्ष में चाहे जो तर्क उपस्थित किए जाएं, किंतु इससे मानव जीवन की वास्तविकता, उसके उद्देश्य और हेतु एवं उच्चतम विकास की सीमाएं आदि के संबंध में एक एकांगी तथा विकृत दृष्टिकोण का प्रसार बड़ी तेजी के साथ होता जा रहा है। साध्य और साधन का विवेक समाप्त हो रहा है। अर्थोत्पादन जीवन का आवश्यक आधार ही नहीं, संपूर्ण जीवन बन गया है। आर्थिक विकास के हेतु धन प्राप्त करने के लिए हम अपनी सेना को भंग कर दें, यह भी सुझाव दिए जाते हैं। सेना के अभाव में यदि हम अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठे तो फिर आर्थिक विकास किसका करेंगे? क्या हमें पराधीनता की स्वर्ण श्रृंखलाएं स्वीकार होंगी? और फिर ये स्वर्ण श्रृंखलाएं लोहे की बेड़ियों में नहीं बदलेंगी यह कौन कह सकता है!

मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और उसमें अर्थ का स्थान निश्चित न होने के कारण हम उस मार्ग का भी ठीक निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर चलकर श्री और समृद्धि का उपभोग कर सकें। साध्य का पता लगे बिना साधन का निश्चय कैसे हो सकता है? हमारी परंपरा और संस्कृति हमें बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं का पिंड नहीं अपितु वह एक आध्यात्मिक तत्त्व है, जिसने भौतिक शरीर धारण कर रखा है। अतः मंदिर की सब प्रकार से चिंता करते हुए भी उसका मंदिरत्व उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति के कारण है तथा मूर्ति का श्रृंगार, धूप-दीप, नैवेद्य, अर्चन आदि उसमें आरोपित देवत्व के कारण हैं, इस तथ्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यदि मंदिर की रक्षा और निर्माण में मूर्ति को भूल गए तो हमारा संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। किंतु जिस पश्चिम का अनुकरण कर हम अपने अर्थनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, वहां जीवन के इस सर्वसंग्राही भाव के लिए कोई स्थान नहीं। फलतः आज हमारे मन, वचन और कर्म में अंतर्विरोध उत्पन्न हो गया है। अंतश्चेतना और बाह्यकर्म दो विरोधी दिशाओं में खींच रहे हैं। यह संघर्ष हमें अपनी संपूर्ण शक्ति से आर्थिक समृद्धि की आज की योजनाओं को पूर्ण करने में भी जुटने नहीं देता। जो कुछ हम करते हैं, वह अन्यमनस्क भाव से और जब हमें अपने प्रयास सफल होते हुए नहीं दिखते तो मन में एक विफलता, आत्मज्ञान और आत्मविश्वासहीनता का भाव उत्पन्न होता है। इस भाव को हम प्रचारतंत्र से, वास्तविकता से आंखें मूंदकर, दूसरों को अपनी असफलता के लिए दोषी ठहराकर, अवास्तविक समस्याओं और संकटों का भूत खड़ा करके तथा हवाई आदर्शों और भविष्य की अधिकाधिक स्वर्णिम कल्पनाजनित आशाओं से दबाने का प्रयत्न करते हैं। फलतः हमारा मानस अधिकाधिक उद्विग्न होता जाता है। हम यथार्थ की भूमि से दूर हटते जा रहे हैं। इस गुत्थी को सुलझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

पश्चिम के अर्थशास्त्र की अनुकूलता

जीवन के विभिन्न आदर्शों के कारण ही नहीं, देश और काल की भिन्न परिस्थितियों के कारण भी हमारे आर्थिक विकास का मार्ग पश्चिम से भिन्न होना चाहिए। किंतु हम मार्शल और मार्क्स से बुरी तरह बंध गए हैं। अर्थशास्त्र के जिन नियमों की उन्होंने विवेचना की उन्हें हम शाश्वत मानकर चल रहे हैं। वे व्यवस्था सापेक्ष हैं, जो यह जानते हैं, वे भी उनकी परिधि से बाहर नहीं निकल पाते। पश्चिम की आर्थिक समृद्धि ने उनकी अर्थोत्पादन पद्धति के विषय में हमारे मन में निरपवाद रूप से श्रद्धा उत्पन्न कर दी है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रज्ञों ने इतना विवेचनात्मक साहित्य उत्पन्न किया है कि उसके भार से हम सहज ही दब पाते हैं। हम उससे ऊपर उठ नहीं सकते। इस अर्थ विज्ञान में अनेक ऐसे विवेचन भी हो सकते हैं, जो देश काल व्यवस्था निरपेक्ष हों तथा सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें, किंतु खरे-खोटे की परख कोई पारखी ही कर सकता है। हमारी शिक्षा और दीक्षा इन पारखियों को उत्पन्न नहीं कर सकी है। हमारे अर्थशास्त्री पश्चिम

के अर्थशास्त्र में पारंगत हो सकते हैं, किंतु वे उस अर्थशास्त्र के विकास में कोई ठोस योगदान नहीं दे सके हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस दृष्टि से उनके लिए न तो विचार प्रवण हो सकती है और न प्रयोग भूमि ही। स्वतंत्र भारतीय अर्थशास्त्र के विकास की या तो उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी या उसमें उन्होंने स्वयं को असमर्थ पाया। गांधीवादी तथा सर्वोदयवादी विचारधाराओं में जिस अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है, वह इस आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाता। वह अनिश्चित ही नहीं सामयिक और भूदान आंदोलन के माध्यम के रूप में जनता के सम्मुख आया है। पश्चिम की अर्थव्यवस्था की कुछ बुराइयों की ओर उसने भले ही सफल संकेत किया हो, किंतु भारत के भावी का विधान करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है।

नई परिभाषाएं

पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में से बहुतों ने अर्ध-विकसित क्षेत्रों की समस्याओं पर नया साहित्य प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक एजेंसियों और समितियों ने भी इस विषय में बहुत कुछ कार्य किया है। उन सबके प्रति कृतज्ञ होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि उनका रोग निदान और प्रस्तावित चिकित्सा सही है। यदि वे किन्हीं निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व न भी करते हों तो भी वे अपने पूर्वग्रहों तथा निष्ठाओं से मुक्त होकर पूर्णतः वस्तुनिष्ठ विवेचन कर सकेंगे, यह मानना कठिन है और फिर हमारे मानस की पृष्ठभूमि में हमारी श्रद्धाओं के आधार पर विचार कर सकना तो उनके लिए असंभव सा ही है। अतः इस साहित्य का उपयोग भी हमें सावधानी से ही करना होगा। हम यह भी नहीं भुला सकते कि पश्चिम के सबल राष्ट्र अपने हितों का संरक्षण करने के लिए नई-नई उपाय योजनाएं कर रहे हैं। उपनिवेशवाद और राजनीतिक गुलामी जहां बीते युग की चीजें बनती जा रही हैं, वहां आर्थिक और वैचारिक आधार पर देशों को अपने अधीन बनाए रखने के गूढ़ उपाय अपनाए जा रहे हैं। फलतः शब्दों की परिभाषाएं बदल रही हैं। पूंजी विनियोग आर्थिक सहायता के नाम से पुकारा जाने लगा है, तो कुछ राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के चोले में अपने पग बढ़ाना उपयुक्त समझा है। यह भी सच है कि हम इन राष्ट्रों द्वारा बढ़ाए गए सहायता के प्रत्येक हाथ को शक़ की नज़र से देखकर झटक नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के हित पूरक हों और कभी सार्वभौम परिस्थितियां किसी पग विशेष के लिए विवश करें। किंतु हमारा हित और अहित किसमें है, इसका भी तो तब तक ज्ञान नहीं हो सकता, जब तक हम अपनी व्यवस्था की भली-भांति मीमांसा न कर लें।

निहित स्वार्थ

पाश्चात्य अर्थशास्त्र के भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त भारत में ऐसे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिनके हित पाश्चात्य अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। पिछले सौ वर्षों में जिस अर्थव्यवस्था का भारत में विकास हुआ, उसने भारत और पश्चिम के औद्योगिक देशों की व्यवस्थाओं को एक-दूसरे का पूरक बनाया। इसमें भारत के हितों का संरक्षण नहीं हुआ, बल्कि उसका बराबर शोषण ही होता रहा। किंतु इस शोषण की क्रिया में पाश्चात्य आर्थिक हितों ने भारत के कुछ वर्गों को भी अपने अभिकर्ता के रूप में साझीदार बना लिया। प्रारंभ में व्यापारी और कमीशन एजेंट के रूप में और बाद में कुछ अंश में उद्योगपति, स्वतंत्र अथवा साझीदार के रूप में इनके हित संबंध विदेशी आर्थिक हितों के साथ बंध गए। इस वर्ग का देश के आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रभुत्व रहा है। आज भी संख्या तथा देश की आर्थिक आय में उनका योगदान कम होते हुए भी वे समाज और देश के अर्थ जीवन पर भारी प्रभाव रखते हैं। इस वर्ग की आकांक्षाएं निश्चित हैं। वे अधिकाधिक अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। समाज के सर्वसामान्य जीवन पर उसका क्या परिणाम होगा, इसकी उन्हें चिंता नहीं। पाश्चात्य अर्थशास्त्र के भारतीय विद्वानों से उनका सहज ही समसंयोग मेल बैठ जाता है। भारत के सभी समाचार-पत्र, विशेषकर अंग्रेज़ी के, उनके प्रभाव क्षेत्र में हैं। ये सब मिलकर जान या अनजान में ऐसा मायाजाल रच देते हैं कि साधारण जन उसमें से निकल ही नहीं पाता।

शासन की सीमाएं

शासन का भी जैसा स्वरूप है, वह इस इंद्रजाल से नहीं बच पाया। प्रथम तो प्रशासन का पूरा ढांचा हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला। हम उसे न तो बदल सकते थे और न बदल पाए। जब कांग्रेस के नेताओं ने भी 1947 के बाद अपनी राष्ट्रीयता केवल खादी के कुरते और टोपी तक ही सीमित कर दी तथा शेष अपनी बातों में प्रगति के पश्चिमी मानदंडों को ही उत्तरोत्तर स्वीकार कर लिया, तो देश के भृत्यवर्ग के लिए भी अपनी पुरानी विचार परंपराओं से जकड़े रहना आवश्यक हो गया। हमारे नियोजकों का आर्थिक चिंतन इसी परिधि में चक्कर काटता रहता है। फिर विदेशी सहायता, विदेशी विशेषज्ञों की सम्मतियों तथा विदेशी जीवन का चित्ताकर्षक बाह्य स्वरूप तथा थोड़ी अवधि में कुछ कर दिखाने की राजनीतिक आवश्यकताओं ने उनको जन-जीवन से दूर हटाकर उसकी समस्याओं का यथार्थ आकलन करने में अक्षम बना दिया। फलतः योजना के बाद योजनाएं बनाई जा रही हैं, किंतु हम जनसाधारण के जीवन में सुख और समाधान की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

मौलिक विचार की आवश्यकता

अतः आवश्यकता है कि हम अपने जीवन-दर्शन का विचार कर भारतीय अर्थव्यवस्था का मौलिक निरूपण करें तथा आज की समस्याओं को यथार्थ की कंटकाकीर्ण, ऊबड़खाबड़ किंतु ठोस भूमि पर खड़े होकर सुलझाएं। भारत के 'स्व' का साक्षात्कार किए बिना हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। यदि किसी क्षेत्र में संयोगवश थोड़ी-बहुत सफलता मिल भी गई तो उसका परिणाम हमारे लिए हितकर नहीं होगा। हम परानुकरण की ओर अधिक प्रवृत्त होंगे। अपने स्वत्व और सामर्थ्य के विकास के स्थान पर परावलंबन का भाव हमारे मन में घर कर जाएगा। आत्महीनता का यह भाव घुन की तरह राष्ट्र की जड़ें खोखली कर देगा। इस प्रकार जर्जर मूल राष्ट्र कभी झंझावातों में खड़ा नहीं रह सकता। यदि हमें देश का विकास करना है तो इस प्रश्न का अंतर्मुख होकर विचार करना ही होगा। यदि उसमें कुछ देर भी लगे तो भी वह स्थायी एवं सर्वहितकर हल होगा। ■

('भारतीय अर्थ-नीति विकास की एक दिशा' से साभार)

रवींद्रनाथ टैगोर

(7 मई, 1861 – 7 अगस्त, 1941)

रवींद्रनाथ टैगोर विश्व कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबल पुरस्कार विजेता हैं। टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। श्री टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें 'गीतांजलि' के लिए साहित्य के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को दो देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। भारत का राष्ट्र-गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं।

रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 7 मई, 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। वे अपने माता-पिता की तेरहवीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से 'रबी' बुलाया जाता था। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1978 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन कालेज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। उनका 1883 में मृणालिनी देवी के साथ विवाह हुआ। रवींद्रनाथ ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सहित दर्जनों देशों की यात्राएं की थी। 7 अगस्त 1941 को देश की इस महान विभूति का देहावसान हो गया।

बचपन से ही उनकी कविता, छन्द और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता आठ साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल सोलह साल की उम्र में उनकी लघुकथा प्रकाशित हुई थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगद्रष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूरबी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनश्च, वीथिका शेषलेखा, चोखेरबाली, कणिका, नैवेद्य मायेर खेला और क्षणिका आदि शामिल हैं।

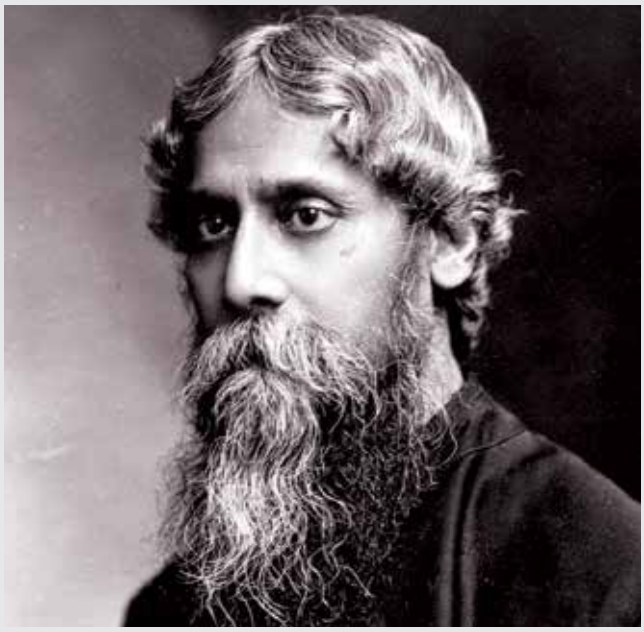

बहुआयामी प्रतिभा

रवींद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण वह सही मायनों में विश्वकवि थे। रवींद्रनाथ ने देश और विदेशी साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि को अपने अंदर समाहित कर लिया था और वह मानवता को विशेष महत्व देते थे। इसकी झलक उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है।

उनके मानवतावादी काव्य ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। दुनिया की तमाम भाषाओं में आज भी टैगोर की रचनाओं को पसंद किया जाता है। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नयी बहार लेकर आई। साहित्य की शायद ही कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचनाएं नहीं हों। उन्होंने कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में रचना की। उनकी कई कृतियों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ। रवींद्रनाथ के नाटक भी अनोखे हैं। वे नाटक सांकेतिक हैं। उनके नाटकों में डाकघर, राजा, विसर्जन आदि शामिल हैं।

रवींद्रनाथ की रचनाओं में मानव और ईश्वर के बीच का स्थायी संपर्क कई रूपों में उभरता है। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही प्रकृति का साथ काफी पसंद था। रवींद्रनाथ चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए शांतिनिकेतन की स्थापना की।

रवीन्द्र संगीत

टैगोर ने करीब 2,230 गीतों की रचना की। रवींद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है उनकी रचनाओं में वह अलग-अलग रूपों में उभरकर सामने आया। अलग-अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। ■

भाजपा: देशभक्ति एवं जनसेवा के लिए समर्पित राष्ट्रशक्ति

रामलाल

21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 11 सदस्यों के साथ जनसंघ की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक पार्टी की यात्रा जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के रूप में चली और बढ़ी है। आज भाजपा भारत की संगठनात्मक व चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आज सबसे अधिक सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर भाजपा के हैं। केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है तथा श्री अमित शाह की अध्यक्षता में सबसे अधिक सदस्यता भी भाजपा की है।

यहां तक की यात्रा सहज नहीं हुई। अनेक उतार-चढ़ाव आए। पार्टी के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुखर्जी व पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान हुआ। राष्ट्रीय आंदलनों में अनेक कार्यकर्ता शहीद हुए, घायल हुए, जेल गए। हार-जीत के भी अवसर आए। 1951 से लगातार बढ़त बनाते हुए 1984 में मात्र दो सांसद भी रह गए, फिर भी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। सबने मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया और वर्तमान स्थिति तक लाया है। विचार पर अडिग रहते हुए पार्टी के विस्तार व कार्यकर्ताओं के विकास की चिंता हुई। 1951 से 1975 तक के कालखण्ड में जितने भी आंदोलन हुए उनमें से अधिकांश जनसंघ ने ही किए। सभी आंदोलन राष्ट्रीय एकता-अखण्डता को अक्षुण्ण रखने, सीमाओं की सुरक्षा व भारतीय मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हुए।

जम्मू-कश्मीर में प्रवेश, गोवा मुक्ति, कच्छ का आंदोलन, बेरूवाड़ी आंदोलन व शिमला समझौते के विरुद्ध आंदोलन आदि इसके उदाहरण हैं।

इसमें से पार्टी की राष्ट्रवादी छवि निर्माण हुई। भारत के करोड़ों राष्ट्रवादी मन रखने वालों को लगा कि राजनैतिक दलों में कोई तो है, जो हमारी बात कह रहा है।

जनसंघ ने अपनी राजनीति संगठन बनाने और चुनाव लड़कर सरकार बनाने मात्र के लिए नहीं की। संगठन व सरकार को साध्य नहीं, साधन माना। साध्य रहा लोक कल्याण व समर्थ भारत का निर्माण। 'सशक्त भाजपा-समर्थ भारत' यह पार्टी का ध्येय वाक्य ही बन गया।

1975 में आपातकाल लगने के बाद अटलजी, आडवाणीजी सहित कई प्रमुख नेता व हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। अनेक कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह करके अपने को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। कार्यकर्ता व उनके परिवारों को कई प्रकार की यातनाओं से

गुजरना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं की जेल में ही मृत्यु हो गई। लोकतंत्र की रक्षा की इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य विपक्षी दलों ने साथ मिलकर हिम्मत से लड़ा। चुनावों की घोषणा होने पर विभिन्न विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। बड़ा दल होने के बाद भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय स्वीकार किया। तानाशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह प्रयत्न सफल हुआ तथा मार्च 1977 में जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। दुर्भाग्य से यह प्रयोग लम्बा नहीं चल पाया। दोहरी सदस्यता के विषय को लेकर जनसंघ के सभी नेता जनता पार्टी से अलग हुए तथा 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई। उन्होंने मुम्बई में घोषणा की ''अंधेरा छटेगा - सूरज निकलेगा - कमल खिलेगा''।

इसी मध्य राम जन्मभूमि का आंदोलन पूज्य संतों के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। भारत की राजनीति में से छद्म धर्मनिरपेक्षता के चेहरे को उजागर करने तथा राष्ट्रीय मान बिन्दुओं के प्रति आस्था निर्माण करने के लिए आडवाणीजी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा प्रारम्भ की। इसे प्रचंड जन समर्थन मिला। इस यात्रा से जहां प्रबल जन-जागरण हुआ वहीं राजनीति की दिशा ही बदल दी। उसका परिणाम आगे के चुनावों में हुआ। 1989 से लेकर आज तक (2009 छोड़कर) भाजपा के सांसदों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1989 के पश्चात् भाजपा कई प्रदेशों में भी सरकार में आई तथा केन्द्र में भी पुनः पहले 13 दिन, बाद में 13 महीने और फिर पूरे 5 वर्ष के लिए ए.डी.ए. की सरकार बनी।

भाजपा सरकारों ने जहां अनेक जन कल्याणकारी काम किए वहीं राष्ट्रीय गौरव व सम्मान को बढ़ाने के प्रयत्न भी चलते रहे।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर लाल चौक (श्रीनगर) तक एकता यात्रा निकालना राष्ट्रभाव के जागरण का अनूठा प्रयास था। पूरा भारत तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्रगौरव के भाव के साथ खड़ा हो गया।

भारत ही नहीं पूरे विश्व में राष्ट्रगौरव का भाव उस समय हिलोरें लेने लगा जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ तथा अटल जी अनेक बड़े देशों की आर्थिक पाबंदियों के समक्ष झुके नहीं। किसी भी देश के नागरिकों का अपने देश की सेना व सुरक्षाबलों के प्रति सम्मान हमेशा ही रहना चाहिए। कारगिल युद्ध के पश्चात् शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर जिस सम्मान के साथ सरकार ने उनके घरों तक पहुंचाए, उससे भारतीय सेना के शौर्य-पराक्रम के प्रति पूरा भारत नतमस्तक हो गया।

राजनीति में पारदर्शिता व गुणवत्ता लाने हेतु NDA-1 में अनेक सुधारात्मक उपाय हुए। राज्य सभा चुनाव में खुला मतदान, सरकारों में मंत्रिमंडल की संख्या को 15 प्रतिशत पर रोकना आदि। देश को कई प्रकार से जोड़ने के प्रयास हुए, Air, Rail, Road, Mobile connectivity, सबके बाद भी 2004 में पुनः विजय श्री नहीं मिल सकी। फिर भी 2004 से 2014 तक शांत होकर नहीं बैठे। पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लम्बी लड़ाई लड़ी। जनहित के अनेक मुद्दों पर स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन हुए।

इसी मध्य गुजरात सुशासन व विकास की दृष्टि से मॉडल प्रदेश बना तथा गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री नरेन्द्र मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर उभरी। पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनकी अगुवाई में, सभी ने कड़ा परिश्रम किया। जनता

के मन में कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई थी। लोगों ने कांग्रेस को घोटाले और भ्रष्टाचार का प्रतीक मान लिया। स्वच्छ व पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्रदान किया। 26 मई 2014 को 30 वर्ष बाद किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी।

इन चार वर्षों में संगठन का चहुंमुखी विस्तार हुआ। नये-नये आयाम संगठन में जुडे। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर हमारी केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकारों ने गरीब कल्याण को केन्द्र में रख कर काम किया।

इन योजनाओं का परिणाम हुआ कि देश की गरीब जनता को लगा कि पहली बार हमारे बारे में कोई सरकार ईमानदारी से सोच रही है। योजनाएं गांव, शहर, कस्बे सहित समाज के सभी वर्गों के लिए बनीं। एक तरफ स्मार्ट सिटी की योजना बनी, तो दूसरी और Soil Health Card के साथ फसल बीमा की चर्चा हुई।

किसानों को लागत मूल्य के 1.5 गुना दाम देने की चर्चा हुई है, तो देश के 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 5 लाख के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा में लाया जा रहा है। किसानों व मजदूरों के हित में इस प्रकार की अनेक योजनाएं चल रहीं हैं। अगले कुछ वर्षों में सभी गांवों में तथा सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह जहां स्वच्छता जन-अभियान बन गया है, वहीं सभी घरों में शौचालय निर्माण का कार्य भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सभी घरों तक गैस चूल्हा पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे पूरा घर धुंआ मुक्त होकर सभी का स्वास्थ्य रक्षण हो सके। सामान्य व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने के साथ-साथ एक साथ 100 उपग्रह छोड़ने की उपलब्धि इस सरकार के खाते में है। भारत की जनता को यह भरोसा बन रहा है कि एक पार्टी व उसकी सरकार जहां भ्रष्टाचार से मुक्त होकर सुशासन के साथ विकास के रास्ते पर चल रही है, वहीं राष्ट्र की रक्षा के प्रति संकल्पित होकर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने में भी सफल हो रही है।

बड़ा दल होने के बाद भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय स्वीकार किया। तानाशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह प्रयत्न सफल हुआ तथा मार्च 1977 में जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। दुर्भाग्य से यह प्रयोग लम्बा नहीं चल पाया। दोहरी सदस्यता के विषय को लेकर जनसंघ के सभी नेता जनता पार्टी से अलग हुए तथा 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई। उन्होंने मुम्बई में घोषणा की "अंधेरा छटेगा - सूरज निकलेगा - कमल खिलेगा"।

राजनैतिक दल 2000 रुपये से अधिक चंदा नकद नहीं ले सकते जैसा निर्णय स्वच्छ राजनीति की ओर एक कदम है। जनता को अच्छे लगें ऐसे नहीं, जनता के लिए अच्छे हों ऐसे कठोर निर्णय भी सरकार ने लिये हैं। नोटबंदी व जी. एस. टी. (एक देश-एक टैक्स) ऐसे ही फैसले हैं जो देश के दीर्घकालीन हित में हैं। राजनैतिक नेतृत्व की स्वीकृति से सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक से देश का मनोबल ऊंचा हुआ है।

इसी का परिणाम है पार्टी भी बढ़ रही है तथा चुनावी राजनीति में भी निरंतर अच्छी सफलता मिल रही है। अभी-अभी त्रिपुरा की जीत तो ऐतिहासिक है जहां शून्य से बढ़ कर 3/4 बहुमत की सरकार बनी है। कई राज्यों में पार्टी को मतदाताओं का 50 प्रतिशत के निकट समर्थन मिलना भी महत्वपूर्ण है। यह विजय अभियान निरंतर चलता रहे यही प्रयास सबका है।

दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष में पार्टी के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना बनी। 1 वर्ष व 6 माह हेतु 3730 विस्तारक व 15 दिन हेतु 272958 अल्पकालीन विस्तारक निकले, जिन्होंने 613947 बूथों पर सम्पर्क किया। 15 करोड़ से अधिक पत्रक बंटे तथा 4 करोड़ पुस्तिकाएं वितरित कीं। नीचे तक पार्टी की विचारधारा व भाजपा सरकारों की उपलब्धियों की चर्चा घर-घर तक की गई।

इसके परिणामस्वरूप पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय व प्रभावी बनाने के साथ मतदाता सूची के एक-एक पन्ने का प्रमुख बनाने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ा है। बूथ समिति व पन्ना प्रमुख पार्टी की ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी भी चुनौती का उत्तर बनने की सामर्थ्य रखती है।

पार्टी ने हमेशा देश की राजनीति में राष्ट्र-रक्षा, लोकतंत्र रक्षा, संस्कृति व मानबिंदुओं की रक्षा, राष्ट्र गौरव के साथ सुशासन व विकास का एजेंडा सेट किया है। भाजपा के कारण वशंवाद, जातिवादी व तुष्टीकरण की नीति समाप्ति की ओर चली गई। 38 वर्ष की पार्टी की यात्रा कई कठिन दौर से गुजरी है। अनेक कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है।

पार्टी के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की पुण्याई व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान को स्मरण करते हुए सभी सदस्यों के लिए संकल्प लेने का दिन है कि सफलता हमें प्रसन्नता देने वाली तो है, किन्तु हम संतोष मानकर बैठेंगे नहीं।

अधिक ऊर्जा के साथ पार्टी को सर्वदूर पहुंचाकर राष्ट्रभाव का जागरण करेंगे तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की भावना के साथ जनसेवा व राष्ट्रसेवा के लिए हमेशा अपने को समर्पित रखेंगे। ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) हैं

प्रगति की समीक्षा और चर्चा

विनय सहस्त्रबुद्धे
धीरज नय्यर

पिछले अंक से जारी...

अप्रत्याशित और रिकॉर्ड तोड़ बारिश से उत्तर भारत में रबी की फसल के बर्बाद होने के तुरंत बाद 25 मार्च, 2015 को पहला प्रगति सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रभावित किसानों के लिए राहत सुनिश्चित करना स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता थी और उस सम्मेलन में भी इस पर चर्चा हुई। उन्होंने सार्वजनिक शिकायतों के दो सेट भी लिए, जिनमें (क) निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान और (ख) आयकर रिफंड से संबंधित करीब 20 लोग शामिल थे। शिकायतों का तत्काल निवारण किया गया (विशेष रूप से यह पाया गया कि प्रगति के माध्यम से हस्तक्षेप प्रणालीगत सुधारों की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों)।

राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी से एक प्रोजेक्ट को स्वीकृति और नवी मुंबई हवाईअड्डे के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी सुना गया था। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की छः परियोजनाओं, जिनमें एक दर्जन से अधिक मंत्रालय और 13 राज्य शामिल थे और जो विभिन्न कार्यवाही या अनुमतियों में देरी के कारण लटकी हुई थीं, को संबोधित किया गया था। कुछ समस्याओं को तो बैठक के दौरान ही हल कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने स्कूल शौचालय कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अभियान में बाधाओं के बारे में भी चर्चा की और तदानुसार निर्देश जारी किए। जब तक मामला पूर्ण रूप से हल नहीं हो जाता तब तक उसका फॉलोअप सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों को प्रगति प्रणाली में भी रखा गया है।

जून 2017 तक, प्रगति की 19 बैठकें हो चुकी थीं और विभिन्न बाधाओं के कारण वर्षों से लंबित पड़ीं 28,31,000 करोड़ की 167 केंद्रीय और राज्य सरकार की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और उनमें तीव्रता लाई गई। उनमें से ज्यादातर महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाएं रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली, कोयला और नागरिक उड्डयन से सम्बंधित थीं। इसके अलावा, 16 मंत्रालयों/विभागों के 38 प्रमुख कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई। 22 अप्रैल, 2015 को हुई प्रगति की दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे को लेकर म्यामांर और थाईलैंड के भारतीय राजदूतों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तर-पूर्वी राज्यों का समग्र विकास, कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बुनियादी परियोजनाओं में तेजी लाने पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल में रेलवे के उपक्रमों पर भी चर्चा की। बाद की एक बैठक में वह भारत की एक्ट ईस्ट नीति के मुख्य स्तंभों में से एक म्यांमार में रीह-टेडिम सड़क परियोजना का वर्णन करेंगे और इसे समय पर पूरा करने का आग्रह करेंगे।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रगति के तहत बातचीत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच उस बाधा को दूर करने के लिए थी, जो निर्णय लेने में आड़े आती थी और इस योजना के पीछे सरकारी प्रक्रियाओं को गति देने के तरीकों को खोजने का विचार सबसे अहम था। उदाहरण के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि आदिवासी बस्तियों की पहचान में तेजी लाने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आदिवासियों को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जमीन का अधिकार मिल सके। दूसरी प्रगति बैठक में भी सार्वजनिक शिकायतों पर चर्चा की गई जो एलपीजी वितरण और बीएसएनएल सेवाओं से संबंधित थीं। दोनों विभागों को चेतावनी दी गई और एक ऐसा सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा गया कि भविष्य में ऐसी समस्याएं पैदा न हों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी कुछ जन अनुकूल प्रयासों के लिए सराहना भी मिली।

27 मई को हुई अगली बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए कार्य कर रहा है और समस्या सुलझाने व तीव्र कार्यान्वयन के लिए प्रेरित कर रहा है। हालांकि, पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट के लाभों में होने वाली देरी के मामले में उदासीन माहौल देखकर वह बहुत चकित हुए। प्रत्येक प्रगति बैठक में बुनियादी विकास पर प्रमुखता से चर्चा की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार में देरी उन विशिष्ट मुद्दों में से एक था जिसने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय को इसे सुलझाने के लिए कहा। चौथी बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए बधाई दी। हालांकि, लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों से होने वाली समस्याओं से वे निराश हुए और सुझाव दिया कि अदालत में मामलों के दौरान इन मुकदमों के नतीजों पर प्रकाश डालने से मदद मिल सकती है।

अपने अनुभवों के आधार पर उनका दृष्टिकोण विशिष्ट रूप से व्यावहारिक रहा। ओडिशा में सड़क और रेल संपर्कों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ओडिशा (नबाकलेबरा), मध्य प्रदेश (सिंहस्थ) और महाराष्ट्र (कुंभ) में प्रमुख त्योहारों की शुरुआत हुई, इसलिए परिवहन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अनुकरणीय व्यवस्थाओं पर काम किया जाना चाहिए। विशेष रूप से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) ने

प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्हें असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में तीन पुलिस स्टेशनों से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका एक डेमो भी दिया गया, जिसके अंत में उन्होंने इसके उन्नत स्तरीय परिष्कार की मांग की और राज्यों को इस सिस्टम को उच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा।

बैठक में विभिन्न जन शिकायतों पर भी ध्यान दिया गया जिनमें रेलवे में भ्रष्टाचार, डाक विभाग में अक्षमता और छात्रवृत्तियों तथा पासपोर्ट के वितरण में देरी प्रमुख हैं। वे जानना चाहते थे कि छात्रों को समय पर उनके फेलोशिप और छात्रवृत्ति का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा था और उन्होंने छात्रों को मिलने वाले लाभों को आधार से जोड़ने की प्रगति के बारे में भी पूछा। पासपोर्ट सेवाओं के संबंध में, आवेदनों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा गया ताकि पासपोर्ट मंजूरी में तेजी लाने के तरीकों की जांच की जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पॉलिसी के लाभ, मनीऑर्डर, बचत खाता ब्याज और चिट्ठियां सही समय पर पहुंचनी चाहिए और इससे समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समाज के सबसे गरीब वर्गों को प्रभावित करता है। यह बताते हुए कि डाक सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है, उन्होंने पूछा कि क्या चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है और डाक सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पॉलिसी के लाभ, मनीऑर्डर, बचत खाता ब्याज और चिट्ठियां सही समय पर पहुंचनी चाहिए और इससे समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समाज के सबसे गरीब वर्गों को प्रभावित करता है। यह बताते हुए कि डाक सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है, उन्होंने पूछा कि क्या चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है और डाक सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए।

उन्हें ई-कॉमर्स से संबंधित बहुत शिकायतें मिलीं, जैसेकि टिकट और होटल बुकिंग, और कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी ताकि दस दिनों के भीतर उनका समाधान हो सके। इसी तरह, दूरसंचार ग्राहकों ने खराब सेवा गुणवत्ता, कनेक्टिविटी और लैंडलाइन कनेक्शनों के काम न करने की शिकायत की। करदाताओं की शिकायतों के चलते आयकर विभाग भी स्क्रूटिनी के लिए आया था। रेलवे को कहा गया कि वह भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्हें सभी शिकायतों और प्रश्नों के लिए एक टेलीफोन नंबर स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया। मजदूरों और ईपीएफ लाभार्थियों की शिकायतों के चलते ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम आयुक्तों को भी आना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मजदूरों को उनके वैध बकाया प्राप्त करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने श्रम मंत्रालय से एक ऐसी प्रणाली शुरू करने के लिए भी कहा जिसमें कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ को अंतिम रूप देना एक साल पहले ही शुरू हो जाए। असामयिक मृत्यु के मामले में, दावों के प्रसंस्करण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पीएमओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल था। उन्होंने सीजीएचएस के तहत आने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों और बच्चों के सार्वभौमिक प्रतिरक्षण के लिए मिशन इंद्रधनुष की समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया कि एनसीसी और नेहरू युवा केन्द्र जैसे युवा संगठनों को टीकाकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग की शुरुआत की और सभी मुख्य सचिवों और सचिवों को अक्टूबर 2016 की विश्व बैंक की रिपोर्ट का अध्ययन करने और उनके संबंधित विभागों और राज्यों में सुधार के दायरे का विश्लेषण करने के लिए कहा। इस संबंध में हुई प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और नवीनतम रैंकिंग में भारत पहली बार पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ और किसी भी देश द्वारा 30 अंकों की दुर्लभ वृद्धि देखने को मिली।

समीक्षा के लिए आने वाली अन्य योजनाओं में - पिछड़े क्षेत्रों, खासकर उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल, देश भर में सौर-पंपों की स्थापना, बाढ़ के लिए तैयारियां, ई-नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत), प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना - आदि शामिल थीं। ■

जारी...

(उपरोक्त सामग्री सद्य: प्रकाशित पुस्तक
'द इनोवेशन रिपब्लिक' से साभार प्रस्तुत है)

भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई

संजीव कुमार सिन्हा

कर्नाटक विधानसभा चुनाव–प्रचार जोरों पर है। पूरा प्रदेश चुनावी रंग में रंग गया है। प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली हैं। राजनेता प्रचार–प्रसार में जुट गए हैं। यहां तीन प्रमुख दल हैं – कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर)। यह चुनाव काफी अहम हो गया है, इसलिए देशभर के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हैं। पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के यशस्वी नेतृत्व में पार्टी दिनोंदिन नई उंचाइयां प्राप्त कर रही है। आज भाजपा केंद्र में जहां अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, वहीं देश के कुल 22 राज्यों में भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। इस क्रम में अब बड़े राज्यों में सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस की सरकार बची है। यहां के नतीजे इसलिए मायने रखते हैं, क्योंकि इसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगभग एक साल बाद केंद्र में भी आम चुनाव होने हैं।

कर्नाटक में भाजपा ने इस बार श्री बी. एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया है। दक्षिण भारत में भाजपा को सशक्त करने वालों में उनका अहम योगदान रहा है। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे कर्नाटक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।

कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए 12 मई को राज्य में मतदान होना है और वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा 15 मई को होनी है। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से आचारसंहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ–साथ वीवीपैट मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात ये है कि इस बार कर्नाटक में सभी ईवीएम पर प्रत्याशियों की तस्वीर भी लगी होगी। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। चुनावी खर्च को लेकर भी आयोग सभी पार्टियों पर पैनी नजर रखेगा। एक उम्मीदवार चुनाव में 28 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा।

राज्य की कुल जनसंख्या 6.4 करोड़ हैं, जिसमें 4.9 करोड़ वोटर हैं। युवा मतदाताओं की तादाद 15.4 लाख है।

2013 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 36.53 वोट प्रतिशत के साथ 122 सीटें, भाजपा को 19.89 वोट प्रतिशत के साथ 44 और जेडीएस को 20.19 प्रतिशत वोट के साथ 40 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके एक साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य की 28 सीटों में से 17 पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस के खाते में 9 सीट और जेडीएस को 2 सीटें मिली थीं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तीनों प्रमुख दल 'रथयात्रा' के माध्यम से प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 'नव कर्नाटक निर्माण परिवर्तन यात्रा' निकालकर पूरे प्रदेश में जन–जागरण किया। इसका नेतृत्व श्री बी.एस. येदियुरप्पा ने किया। कांग्रेस ने 'जन–आशीर्वाद' रैली निकाली, वहीं जनता दल (सेक्युलर) ने

''कर्नाटक विकास वाहिनी'' के माध्यम से प्रदेश का प्रवास किया।

इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दे हैं – विकास, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, खराब कानून–व्यवस्था, राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं की हत्या।

कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार में व्याप्त कुशासन के चलते लोगों में आक्रोश है। सिद्धारमैया सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उनकी सूची में कर्नाटक शीर्ष पर है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा सरकारी कामों को कराने के लिए दिए जाने वाले घूसों के आधार पर भ्रष्ट राज्यों की एक सूची तैयार की गई। इस सर्वे में 20 राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 3,000 लोगों की राय ली गई। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान कम से कम एक बार करीब एक तिहाई लोगों को सरकारी काम कराने के दौरान भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। श्री सिद्धारमैया 40 लाख की घड़ी पहनते हैं। उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में रेड पड़ रही है, कई बेनामी संपत्तियां पकड़ी गईं, मंत्रियों पर हत्या तक के आरोप लगे।

किसानों की आत्महत्या बड़ा मुद्दा है। राज्य में पिछले पांच सालों में 3515 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक अप्रैल 2013 से लेकर नवंबर 2017 के बीच 3515 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य में कृषि संकट एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। प्रदेश में कानून–व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 24 कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं कर दी गईं, लेकिन सरकार ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। दो साल पहले बुद्धिजीवी एमएम कलबुर्गी की हत्या हुई थी। पिछले साल पत्रकार गौरी लंकेश की भी हत्या हुई। इस मामले में भी कर्नाटक पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।

सिद्धारमैया सरकार की नाकामियों के प्रति लोगों में बेहद आक्रोश हैं। इससे हताश होकर कांग्रेस सरकार ने लिंगायत को अल्पसंख्यक का दर्जा देना तय कर दिया। यहां प्रश्न उठता है कि अगर सिद्धारमैया इतने गंभीर थे तो चार साल तक उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया और चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा कर दी। यही नहीं, केंद्र की यूपीए सरकार भी लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुकी है।

भाजपा को केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हुए काम का लाभ मिल रहा है। राज्य की जनता जिन केंद्रीय योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई है, उनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना और सुकन्या समृद्धि योजनाएं शामिल हैं। 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक सरकार को 2,19,506 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जो यूपीए सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उज्ज्वल डिस्कॉम योजना के लिए लगभग 4300 करोड़, डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड के तौर पर 34533 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 960 करोड़, अमृत योजना के लिए 4953 कोर्ड, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 204 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2600 करोड़, स्वायल हेल्थ कार्ड के लिए 31 करोड़, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 405 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 219 करोड़ और नये सड़कों के निर्माण के लिए 50 प्रोजेक्ट्स हेतु लगभग 27 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह कर्नाटक को 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि के अलावा विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं में 1,10,000 करोड़ रुपये और अधिक मिले हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुद्रा योजना के तहत 39 लाख लोन जारी हुये हैं, जिसके अंतर्गत 39,441 करोड़ रुपये निर्गत किये जा चुके हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 6.12 लाख गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं,और 11 करोड़ जन–धन एकाउंट खोले गए हैं। इन सभी योजनाओं के चलते राज्य में लोगों का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है।

जिस प्रकार से सिद्धारमैया सरकार के शासन में भ्रष्टाचार हुए हैं, सांप्रदायिक राजनीति तेज हुई है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है, कानून–व्यवस्था ध्वस्त हुए हैं, राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं की चुन–चुनकर हत्याएं हुई हैं, इससे कर्नाटक की जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ जमकर अभियान चलाए। श्री बी. एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में 'परिवर्तन यात्रा' निकाली गई, जिसे अभूतपूर्व जन–समर्थन मिला। जनता प्रदेश में बदलाव चाह रही है।

जिस प्रकार से सिद्धारमैया सरकार के शासन में भ्रष्टाचार हुए हैं, सांप्रदायिक राजनीति तेज हुई है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है, कानून–व्यवस्था ध्वस्त हुए हैं, राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ताओं की चुन–चुनकर हत्याएं हुई हैं, इससे कर्नाटक की जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ जमकर अभियान चलाए। श्री बी. एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में 'परिवर्तन यात्रा' निकाली गई, जिसे अभूतपूर्व जन–समर्थन मिला। जनता प्रदेश में बदलाव चाह रही है। ■

मैसूरु (कर्नाटक)

'राज्य में विकास की नई इबारत लिखने के लिए भाजपा सरकार बनाइए'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 मार्च को राजेन्द्र कला मंदिर, मैसूरू (कर्नाटक) में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भ्रष्टाचार एवं हिंसा की राजनीति की प्रतीक सिद्धारमैया सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने राज्य के विकास के लिए श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के गठन का मन बना लिया है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैसूरू क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता सिद्धारमैया सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में कई मुद्दों पर काफी नाराजगी है जिसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है। वैसे भी कांग्रेस और भ्रष्टाचार का रिश्ता मछली और पानी सा अटूट रहा है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में कर्नाटक में भ्रष्टाचार की आंधी चल रही है, गलती से भी सिद्धारमैया सरकार यदि रिपीट हो गई तो भ्रष्टाचार की आंधी सुनामी में तब्दील हो जायेगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक की जनता को उठाना होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पांच सालों में राज्य में विकास के सभी मानक नीचे की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा शासित राज्य लगातार विकास की नई कहानी लिख रहे हैं, वहीं कर्नाटक लगातार विकास के मामले में पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अधिक रेवेन्यू आने के बावजूद सिद्धारमैया सरकार इसे नीचे तक पहुंचाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में यदि कोई राज्य सरकार सबसे ज्यादा विफल रही है, तो वह कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है। पिछले चार सालों में राज्य में लगभग 3500 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे साजिश बता रहे हैं, इतना असंवेदनशील बयान मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना।

जनता दल सेक्युलर पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि जेडीएस कर्नाटक में केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, वह कर्नाटक

में सरकार बनाने की स्थिति में तो कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीएस राज्य में परिवर्तन नहीं कर सकती, वह राज्य की जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निजात नहीं दिला सकती, जनता के सामने एकमात्र विकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में एवं श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी जातियों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से संसद में विधेयक लेकर आई थी, इसे लोक सभा में तो हमने पारित करा लिया क्योंकि वहां हमारी बहुमत है, लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन में माइनॉरिटी सदस्य होने की बात कह कर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि काका साहब कालेलकर कमीशन के समय से यह विधेयक लंबित पड़ा हुआ था, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, तब तक उसने तो कुछ किया नहीं और जब हमने इस विधेयक को संसद में पारित कराना चाहा, तब भी वह रोड़े अटका रही है। उन्होंने सिद्धारमैया से प्रश्न पूछते हुए कहा कि आप अपने-आप को ओबीसी नेता कहते हैं तो राज्य की ओबीसी जनता को जवाब दीजिये कि आप अपनी ही पार्टी को समझाने में विफल क्यों रहे? उन्होंने कहा कि केवल और केवल कांग्रेस के विरोध के कारण ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक संसद में अटका हुआ है, इसका जवाब कर्नाटक के पिछड़े समाज को सिद्धारमैया को देना होगा।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में वर्षों से तलवारा और परिवारा जाति को ट्राइबल के अंदर लाने की मांग की जा रही थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार है जिसने इन दोनों प्रमुख जातियों को ट्राइबल का स्टेटस देकर इन जातियों के बच्चों के सुनहरे भविष्य को संजोने का काम किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार के बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के सभी गरीब नागरिकों और किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनायें लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत गरीबों की पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य खर्चे का भार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उठायेगी, इससे देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल तक किसी सरकार ने किसानों को उसकी लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लेने का साहस नहीं दिखा पाई, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों को उनकी उपज के लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं का बहुत सकारात्मक असर देश की गरीब जनता में दिखाई पड़ रहा है। ये योजनायें उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ कर्नाटक के गरीब समाज के सभी लोगों को पहुंचेगा।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में 13वें वित्त आयोग में कर्नाटक को केवल 88,583 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक को 2,19,506 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना में 39,400 करोड़, स्मार्ट सिटी में 960 करोड़, अमृत मिशन के लिए 4,953 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 204 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 239 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 405 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 290 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2,617 करोड़, रेलवे के विकास के लिए 2,197 करोड़ और सड़कों के निर्माण के लिए 27,482 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को विकास के लिए लगभग 80 हजार करोड़ रुपया अलग से दिया गया है, लेकिन ये पैसा कर्नाटक की जनता तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यह सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है।

उन्होंने कहा कि इस पैसे पर कर्नाटक की जनता का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस की ही सोनिया-मनमोहन की सरकार ने कर्नाटक की जनता को उसके अधिकारों से वंचित रखने का पाप किया था, इस पर सिद्धारमैया जी क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कर्नाटक में लगभग 3.50 लाख गैस सिलिंडर वितरित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सिद्धारमैया समझते हैं कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को अलग नाम देकर वे इसे अपनी योजना बता देंगे, तो वे गलतफहमी में हैं क्योंकि कर्नाटक की जनता ये जानती है कि ये सभी योजनायें मोदी सरकार द्वारा देश भर में चलाई जा रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता से अपील करने आया हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में सशक्त येदुरप्पा सरकार बनाइये जो राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जायेगी और विकास की नई ईबारत लिखेगी। ■

'ओबीसी समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अप्रैल को कर्नाटक में कगिनेले डेवलपमेंट अथॉरिटी के नजदीक मैदान में ओबीसी कन्वेंशन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी के कल्याण के लिए उठाये क़दमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी सिद्धारमैया सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंककर श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विकासोन्मुखी सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कनकदास की तपोभूमि और कर्मभूमि में आकर मैं अपने-आप को धन्य समझ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव का बिगुल बज चुका है और राज्य की जनता को यह तय करना है कि महान कर्नाटक के भविष्य की बागडोर किसके हाथ में होगी। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर श्री येदुरप्पा जी के कर्मठ नेतृत्व में किसान, गरीब, दलित और ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए अहर्निश काम करने वाली भाजपा सरकार है, तो वहीं दूसरी ओर वोटबैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर समाज को बांटने वाली कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता के सामने एक ओर तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के सहारे देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दूसरी ओर समाज में झगड़ा करवा कर अंग्रेजों की तरह 'फूट डालो और शासन करो' की नीति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक की जनता को तय करना है कि उन्हें किसको चुनना है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी जातियों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से संसद में विधेयक लेकर आई थी, इसे लोक सभा में तो हमने पारित करा लिया क्योंकि वहां हमारी बहुमत है लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन में माइनॉरिटी सदस्य होने की बात कह कर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि काका साहब कालेलकर कमीशन के समय से यह विधेयक लंबित पड़ा हुआ था, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, तब तक उसने तो कुछ किया नहीं और जब हमने इस विधेयक को संसद में पारित कराना चाहा, तब भी वह रोड़े अटका रही है। उन्होंने सिद्धारमैया से प्रश्न पूछते हुए कहा कि आप अपने-आप को ओबीसी नेता कहते हैं तो राज्य की ओबीसी जनता को जवाब दीजिये कि आप अपनी ही पार्टी को समझाने में विफल क्यों रहे? उन्होंने कहा कि केवल और केवल कांग्रेस के विरोध के कारण ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक संसद में अटका हुआ है, इस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहे कितना भी रोक ले, भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पुनः पारित करके पिछड़े समाज के लोगों को न्याय दिलाकर रहेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के

सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता के अथाह प्यार और समर्थन से यह निश्चित है कि राज्य में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की सशक्त येदुरप्पा सरकार ओबीसी समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम करेगी।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से एक-के-बाद-एक भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले का जो सिलसिला चला है, वह भर्त्सनीय है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में कर्नाटक में 24 से ज्यादा भाजपा एवं संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है जिसमें अधिकांश संख्या ओबीसी कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पार्टी कार्यकर्ताओं के हत्यारों को जेल की सींखचों के पीछे पहुंचाया जाएगा और संवैधानिक तरीके से कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रावधान किया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है। मोदी सरकार द्वारा शुरू किये गए लोक-कल्याणकारी योजनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि योजनायें देश के गरीब और ओबीसी समाज के कल्याण को ही केंद्र में रख कर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अकेले मुद्रा बैंक योजना के तहत कर्नाटक में 98 लाख, अर्थात् लगभग एक करोड़ लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 50 लाख से अधिक ओबीसी समाज के युवा हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में साढ़े तीन लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलिंडर दिया गया है जिसमें से एक लाख ओबीसी समाज की महिलाएं हैं।

श्री शाह ने कहा कि इस बार के बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के सभी गरीब नागरिकों और किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनायें लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत गरीबों की पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य खर्चे का भार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उठायेगी, इससे देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल तक किसी सरकार ने किसानों को उसकी लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लेने का साहस नहीं दिखा पाई, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों को उनकी उपज के लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं का बहुत सकारात्मक असर देश की गरीब जनता में दिखाई पड़ रहा है, ये योजनाएं उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है, पिछले चार सालों में राज्य में लगभग 3500 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कर्नाटक की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आप एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की किसान-मित्र येदुरप्पा सरकार का गठन कीजिये, हम कृषि को प्राथमिकता देंगे और इसे मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या जैसा कदम न उठाना पड़े।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि सिद्धारमैया अपने आप को अहिन्दा नेता कहते हैं, लेकिन उन्हें केवल A अर्थात् अल्पसंख्यकों की चिंता है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने बजट के आवंटन में भी ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय किया है।

मोदी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है। मुद्रा बैंक योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि योजनायें देश के गरीब और ओबीसी समाज के कल्याण को ही केंद्र में रख कर बनाई गई है। अकेले मुद्रा बैंक योजना के तहत कर्नाटक में लगभग एक करोड़ लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 50 लाख से अधिक ओबीसी समाज के युवा हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में 13वें वित्त आयोग में कर्नाटक को केवल 88,583 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक को 2,19,506 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा किमोदी सरकार ने 112 से अधिक गरीब-कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इन योजनाओं को जनता तक पहुंचने ही नहीं देती। उन्होंने कर्नाटक को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने और राज्य में विकास की गति को और तेज करने के लिए जनता से श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। ■

'उत्तर-पूर्व अष्टलक्ष्मी बनने की दिशा में अग्रसर'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 24 मार्च को असम के वेटनरी कॉलेज मैदान, खानपारा में आयोजित बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया और उन्हें पार्टी की अविरल विजयगाथा का असली अधिकारी बताते हुए उनसे 2019 के आगामी लोक सभा चुनाव में नार्थ-ईस्ट की 25 में से 21 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सम्मेलन में असम के सभी 25 हजार बूथ के अध्यक्षों ने भाग लिया। ज्ञात हो कि भाजपा अध्यक्ष आज संगठनात्मक दौरे पर असम में हैं, जहां वे बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कई बैठकों में भाग लेंगे।

बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी पहली जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की ही थी। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र किसी अन्य पार्टी में संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है और यहां छोटे-से-छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि असम में पार्टी ने बूथ अध्यक्ष तक के सफ़र का काम पूरा कर लिया है और पन्ना प्रमुख की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि असम में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मणिपुर में एक साल पहले ही हमारी सरकार बनी और अभी-अभी त्रिपुरा में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक नार्थ-ईस्ट में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज मिजोरम को छोड़ कर उत्तर-पूर्व के सभी हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगियों की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक नार्थ-ईस्ट में भाजपा की इस विजय गाथा का रहस्य पूछते हैं, वास्तव में मेरे बूथ अध्यक्ष ही पार्टी की जीत के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के गत लोक सभा चुनाव में उत्तर-पूर्व से भाजपा को लोक सभा की केवल 8 सीटें ही मिली थीं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में 2019 के आगामी लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ-ईस्ट की 25 सीटों में से कम-से-कम 21 सीटें जीतेंगी और मैं आपके भरोसे मीडिया में इस लक्ष्यांक का निर्धारण कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नेडा (NEDA) का संगठन उत्तर-पूर्व में जिस तरह से फैलता जा रहा है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के आम चुनाव में हमारे नेता और अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता के समक्ष

कहा था कि यदि 2014 में हमें जनादेश मिलता है और हम सरकार बनाते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के पूर्वी हिस्से और उत्तर-पूर्व के विकास को देश के पश्चिमी हिस्से के समकक्ष लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चार सालों में उत्तर-पूर्व में विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया है और असम में विकास की बयार लाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां फूट डालो और राज करो की रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां 'सबका साथ, सबका विकास' करने की रही है और इसी के कारण आज उत्तर-पूर्व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय असम के भारत में बने रहने पर संकट उत्पन्न हो गया था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से डोकलाम में मोर्चा संभाला, उससे पूरे विश्व को एक संदेश गया कि भारत की सीमाओं को कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे उत्तर-पूर्व के अंदर शांति के लिए विशेष प्रयास किये हैं जिसका नतीजा है कि उग्रवाद में लिप्त कई संगठनों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश आजाद हुआ, अपना असम देश के चौथे नंबर का समृद्ध राज्य हुआ करता था, जबकि सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा राज्य की कमान संभाले जाते वक्त कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण असम देश के गरीब राज्यों में चौथे नंबर पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश सीमा विवाद का देश के हित में समाधान किया है, इससे पूरा उत्तर-पूर्व अष्टलक्ष्मी

बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व में दो बड़े पोर्ट बनाए जा रहे हैं जो पूरे नार्थ-ईस्ट के विकास को गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण असम में विकास दिन दुगुनी-रात चौगुनी की रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने असम में जो भ्रष्टाचार की जड़ें जमाई थीं, उसे समूल नष्ट करने का काम सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं श्री सर्बानंद सोनोवाल को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने असम में चुनाव के पूर्व वादा किया था कि हम असम को आतंकवाद से मुक्त बनायेंगे और आज जब देश का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस असम में तीन दिनों तक मनाया जाता है तो न सिर्फ असम, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर आनंद की एक लहर दौड़ पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमने असम के नागरिकों से राज्य को विदेशियों से मुक्त करने की मुहिम शुरू करने का वादा किया था, आज नेशनल सिटीजन रजिस्टर का काम जिस तरह से आगे बढ़ा है, मुझे भरोसा है कि इस कार्य को भी हम जल्द ही पूरा कर लेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 वर्षों तक असम ने सोनिया-मनमोहन की यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री को चुनकर भेजा, असम के राज्यसभा के सदस्य 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे लेकिन असम का विकास नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने असम के विकास के लिए इन चार वर्षों में क्या किया? उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान जब केंद्र में और असम में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तब असम को विकास के लिए 79,741 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में असम को 1,55,292 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जो यूपीए सरकार की तुलना में लगभग 75 हजार करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने असम को स्मार्ट सिटी के लिए 191 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 84 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 99 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 400 करोड़, अमृत मिशन के लिए 591 करोड़, पर्यटन के लिए 227 करोड़, एम्स के लिए 1100 करोड़, रोड कनेक्टिविटी के लिए 15 हजार करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5800 करोड़ रुपये देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना में असम के लगभग 32 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में राज्य के 1.27 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं, 20 लाख से अधिक परिवारों को LED बल्ब उपलब्ध कराया गया है। तकरीबन 9 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी असम में लगभग 2800 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, जबकि 4 सालों के अंदर 2800 में से 2732 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ब्रह्मपुत्र नदी पर 9 किमी लंबा ब्रिज, कौशल विकास केंद्र और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाकर बाढ़ से मुक्त के रास्ते निकालना - न जाने कितनी ही योजनायें राज्य के विकास के लिए मोदी जी ने शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों के अंदर हर 15 दिनों में एक-न-एक केन्द्रीय मंत्री जाते हैं, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां प्रधानमंत्री स्वयं कम-से-कम दो बार न गए हों, पूर्वोत्तर का इतना दौरा आजादी के बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद नार्थ-ईस्ट काउंसिल की पहली बैठक शिलांग में हुई, डोनर मंत्रालय को नार्थ-ईस्ट भेजने का काम मोदीजी ने किया। उन्होंने कहा कि असम की भाजपा सरकार ने भी राज्य के विकास के लिए कई कार्य किये हैं - भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना, असम आदर्श ग्राम योजना, अटल अमृत अभियान, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे ढेर सारे काम श्री सर्बानंद सोनोवाल और श्री हेमंत बिस्व सरमा ने किये हैं।

कांग्रेस की नीतियां फूट डालो और राज करो की रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां 'सबका साथ, सबका विकास' करने की रही है और इसी के कारण आज उत्तर-पूर्व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय असम के भारत में बने रहने पर संकट उत्पन्न हो गया था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से डोकलाम में मोर्चा संभाला, उससे पूरे विश्व को एक संदेश गया कि भारत की सीमाओं को कोई छू भी नहीं सकता।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महज एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि संगठन के आधार पर आगे बढ़ने वाली एक विचारधारा आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम किसी को विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम नहीं करते, हम भारत माता को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी मिशन को लेकर निकली है और मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, दुनिया को यह संदेश देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों से करबद्ध निवेदन करते हुए पन्ना प्रमुख के काम को पूरा करने का आह्वान किया, ताकि भाजपा असम के घर-घर तक पहुंच सके। ■

बीएस-VI ईंधन से वर्तमान बीएस-IV की तुलना में सल्फर का स्तर 80 प्रतिशत घट जाएगा : धर्मेन्द्र प्रधान

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने राजधानी में बीएस-VI ईंधन का उपयोग अप्रैल 2020 के बजाय अप्रैल 2018 से ही करने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा कि बीएस-VI ईंधन से वर्तमान बीएस- IV की तुलना में सल्फर का स्तर पांच गुना कम हो जाएगा यानी इसमें 80 प्रतिशत की कमी होगी, जिसकी बदौलत यह ईंधन अत्यंत स्वच्छ है। इससे सड़कों पर चलने वाले वर्तमान वाहनों, यहां तक कि पुराने वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी काफी घट जाएगा। बीएस-VI ईंधन सीएनजी जैसा स्वच्छ है और कुछ मायनों में तो यह सीएनजी से भी ज्यादा स्वच्छ है। श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 2 अप्रैल को दिल्ली में बीएस-VI अनुरूप ऑटोमोटिव ईंधनों को लांच करने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 01 अप्रैल, 2020 तक देश भर में इन ईंधनों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र के एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हर वर्ष 10,000-30,000 लोगों की मौत हो जाती है। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-VI ईंधन का उपयोग जल्द शुरू कर देने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी और इसकी बदौलत हजारों लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाना संभव हो पाएगा।

हालांकि, इस तरह के उन्नत ईंधनों की उपलब्धता से पूर्ण लाभ उठाने के लिए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बीएस-VI के अनुरूप करना होगा। अतः सड़कों पर चलने वाले वाहनों को यदि बीएस-VI के अनुरूप न किया गया, तो बीएस-VI ईंधन का उपयोग शुरू करने से केवल आंशिक लाभ ही हो पाएगा। मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले से ही भारत में बीएस-VI बना रही हैं और इनका निर्यात विकसित देशों को कर रही हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि ये कंपनियां हमारे अपने देश के लिए भी कुछ ऐसा ही उल्लेखनीय उपाय कर सकती हैं। श्री प्रधान ने सभी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों से उन सभी शहरों में बीएस-VI वाहनों की बिक्री शुरू करने की अपील की, जहां बीएस-VI ईंधन उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय पराली जलाए जाने के साथ-साथ अन्य कारणों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रयासरत है। 2जी एथनॉल संयंत्रों की स्थापना करना, प्राथमिक ऊर्जा के क्षेत्र में गैस की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना, गैस विकास बोलियों का नौवां दौर शुरू करना, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गैस क्षेत्र को अलग करना और अधिक स्वच्छ ईंधनों के लिए विभिन्न उपाय करना मंत्रालय के इन प्रयासों में शामिल हैं।

बीएस-VI ईंधन का उपयोग शुरू करने के साथ ही भारत भी एशिया-प्रशांत राष्ट्रों यथा जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और चीन की छोटी सूची में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि चीन केवल भारी वाहनों में ही बीएस-VI ईंधन का उपयोग कर रहा है। गौरतलब है कि विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की महानिदेशक श्रीमती सुनीता नारायण ने इस सकारात्मक कदम के लिए मंत्रालय की सराहना की। ■

रिश्ते का नया रंग

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा से भारत-नेपाल संबंध को एक नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और भारत ने भी काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों अतीत की कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह बराबरी और परस्पर विश्वास पर आधारित रिश्ते की शुरुआत हुई है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देश बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक रेललाइन बिछाने पर सहमत हुए हैं। आम लोगों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिहाज से भी यह परियोजना काफी अहम मानी जा रही है। भारत नेपाल को अपने जलमार्गों के जरिए समुद्र तक पहुंचने का रास्ता देने पर भी सहमत हुआ है। भारत काठमांडू को कृषि में भी सहायता देने जा रहा है। भारत कृषि के विकास में अपने अनुभव और नई तकनीकों को साझा करेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय भी गए और उन्होंने वहां कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों का जायजा भी लिया। अगर नेपाल में चीन के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है तो भारत को अपनी सभी परियोजनाएं तेजी से पूरी करनी होंगी। तभी वहां की जनता में भी भारत के प्रति विश्वास कायम होगा ।

—(नवभारत टाइम्स, 10 अप्रैल, 2018)

सत्याग्रही से स्वच्छाग्रही, सामूहिकता का बल ही स्वच्छता अभियान

चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी को कदम रखे सौ साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में सत्याग्रहियों की परंपरा की इस धरती से एक और उम्मीद की जा रही है- गंदगी के खिलाफ आंदोलन की। गौर करें तो हमारे समाज द्वारा खुद पैदा किए गए इस दुश्मन के खिलाफ जंग की सख्त आवश्यकता है। स्वच्छ भारत की मुहिम को धार देने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चंपारण की धरती से इस जंग की अपेक्षा रखते हैं तो यह इस क्षेत्र विशेष के प्रति सम्मान है। यदि इस अभियान को सामूहिकता का रूप दिया जाए तो सुखद परिणाम की कल्पना की जा सकती है। खुले में शौच से निजात के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसकी गति धीमी। इसकी बड़ी वजह है जागरूकता का अभाव। यदि जागरूकता पैदा करने में ही हम अपनी भूमिका तय कर लें, तो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। यदि नाले-नालियों में ठोस अपशिष्ट और पॉलीथिन डालने पर नियंत्रण कर लें, तो जाम की वजह से सड़कों पर उफन आने वाली गंदगी पर लगाम लग जाएगी।

—(दैनिक जागरण, 9 अप्रैल, 2018)

नेपाल के साथ

भारत और नेपाल के रिश्ते जैसे रहे हैं, उसकी तुलना किसी और द्विपक्षीय संबंध से नहीं की जा सकती। भारत और नेपाल न सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि और भी बहुत-से तार उन्हें जोड़ते हैं। दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई है। भारत ने नेपाल के लोगों को अपने यहां काम करने और शिक्षा ग्रहण करने जैसी कई अहम सुविधाएं दे रखी हैं। दोनों के बीच दशकों से एक मैत्री संधि चली आ रही है, जो आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता का एक और प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडलों के बीच जलमार्ग और रेलमार्ग के जरिए संपर्क और आवाजाही बढ़ाने पर भी बात हुई। दूसरी तरफ, ओली की यहां आना भारत के लिए भी अहम था, क्योंकि यह आपसी भरोसे की बहाली का मौका था, खुद को आश्वस्त करने का भी, कि नेपाल चीन के पाले में नहीं है। अगर भारत चीन के प्रति नेपाल के आकर्षण को रोकना चाहता है तो उसका पहला तकाजा यह है कि नेपाल में भारत की मदद से शुरू की गई परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी हों।

—(जनसत्ता, अप्रैल 9,2018)

स्फुट विचार...

प्रत्येक देश का अपना मूल्य होता है। उसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। कोई भी देश अपने इन मूल्यों से अलग होकर या अपने देश की सांस्कृतिक मान्यताओं को छोड़कर कोई विदेशी मूल्य और उसकी अवधारणा समाज के ऊपर थोपने का प्रयत्न करता है, तो उस राष्ट्र को उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। इसके परिणाम भी अच्छे नहीं निकलते हैं।

— कुशाभाऊ ठाकरे

आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु अपने भीतर रहते हैं। वे शत्रु हैं- लालच, द्वेष, क्रोध, घमंड और आसक्ति और नफरत।

— महावीर

प्रस्तुति: पंकज आनंद

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

भवानीपटना (ओडिशा) में विशाल रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कगिनेल्ली कनक गुरुपीठ (कर्नाटक) में पूज्य स्वामियों का आशीर्वाद लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

भाजपा स्थापना दिवस पर दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल

राष्ट्रपति भवन में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली का स्वागत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20